Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-18, अंक-01 01-15 जनवरी, 2023 (पाक्षिक) ₹20

'टीआरएस सरकार प्रजातंत्र का गला घोंटने वाली और जन विरोधी सरकार है'

गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह

यह ऊर्जावान टीम गुजरात को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी: प्रधानमंत्री

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 81.35 करोड़ लाभार्थी को नि:शुल्क अनाज देने की दी मंजूरी

भारत की विदेश नीति में 2014 के बाद आया बदलाव

कवालुरु (कर्नाटक) में 15 दिसंबर, 2022 को भाजपा जिला कार्यालय और नौ अन्य भाजपा जिला कार्यालयों का उद्‌घाटन करने के बाद एक विशाल सभा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेतागण

करीमनगर (तेलंगाना) में 15 दिसंबर, 2022 को 'प्रजा संग्राम यात्रा' के समापन पर अभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 13 दिसंबर, 2022 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष बैठक के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

वाराणसी में 16 दिसंबर, 2022 को 'काशी तमिल संगम' के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जी. किशन रेड्डी

कोलकाता में 17 दिसंबर, 2022 को 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

मुंबई में 18 दिसंबर, 2022 को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस युद्धपोत 'आईएनएस मोरमुगाओ' के कमीशन के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

भूपेंद्र पटेल ने ली दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ

06

गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद 12 दिसंबर, 2022 को श्री भूपेंद्र पटेल ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड मैदान में एक भव्य समारोह में पद...

11 'भाजपा 'सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं' की नीति में विश्वास रखती है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 15 दिसंबर, 2022 को...

12 'टीआरएस सरकार प्रजातंत्र का गला घोंटने वाली और जन विरोधी सरकार है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 15 दिसंबर...

17 'वन रैंक वन पेंशन' में पुनरीक्षण, 25.13 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर को 'वन रैंक...

26 केंद्रीय गृहमंत्री ने की भारतीय सेना की वीरता की सराहना एवं विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित...

वैचारिकी

सामूहिकता का भाव / **पं. दीनदयाल उपाध्याय** 24

अन्य

पाकिस्तानी मंत्री की टिप्पणी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन 14

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 81.35 करोड़ लाभार्थी को दिसंबर, 2023 तक निःशुल्क अनाज देने की दी मंजूरी 16

वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में 25.90 प्रतिशत की हुई वृद्धि 18

नौसेना को मिला स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत 'आईएनएस मोरमुगाओ' 19

संयुक्त राष्ट्र ने 'नमामि गंगे' को विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में दी मान्यता 20

'एक देश एक राशन कार्ड' के तहत अब तक किए गए 93.31 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन 21

सांसदों के लिए विशेष लंच के माध्यम से पोषक-अनाज को बढ़ावा देने की बड़ी पहल 22

मोदी स्टोरी 23

पूर्वोत्तर दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए हमारा प्रवेश द्वार हैः नरेन्द्र मोदी 28

'त्रिपुरा गरीबों के लिए घर बनाने में अग्रणी राज्यों में एक है' 29

भारत की विदेश नीति में 2014 के बाद बदलाव आयाः एस. जयशंकर 30

संसद के दोनों सदनों ने नौ विधेयक किए पारित 32

आज़ादी के अमृत काल के दौरान देश के पूर्वी क्षेत्र का भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा 34

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

केंद्र सरकार की बदली प्राथमिकताओं और कार्य-संस्कृति का असर देशभर में दिख रहा है। इस बदलाव का एक बड़ा लाभार्थी नॉर्थ ईस्ट भी है। (18 दिसंबर, 2022)

जगत प्रकाश नड्डा

केसीआर हमेशा कहते रहे हैं कि तेलंगाना एक समृद्ध राज्य है, लेकिन मैं उन्हें सही करना चाहता हूं। आठ साल पहले तेलंगाना एक समृद्ध राज्य था, अधिशेष वाला राज्य था, लेकिन आज आपने इसे एक गरीब राज्य बना दिया है, जो 3.29 लाख करोड़ रुपये के भारी कर्ज में डूबा हुआ है और आपने इसे अंधकार में धकेल दिया है। (15 दिसंबर, 2022)

अमित शाह

आज ही के दिन वर्ष 1971 में भारतीय सेना ने अपनी अद्भुत वीरता व पराक्रम से मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए इतिहास के पन्नों में अपनी एक और शौर्यगाथा को अंकित किया। सेना के बहादुर वीरों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं और देशवासियों को 'विजय दिवस' की शुभकामनाएं देता हूं। (16 दिसंबर, 2022)

राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जहां देश में ईज आफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा दिया, वहीं छोटे कारोबारियों के लिए वे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर आए। मुद्रा लोन के माध्यम से जो राशियां दी गईं उनमें एनपीए (Non Performing Asset) की संख्या सात सालों में केवल 3.3 फीसदी रही है। (17 दिसंबर, 2022)

बी.एल. संतोष

प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन देने को मंजूरी दी है। यह गरीब कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम है। (23 दिसंबर, 20222)

डॉ. के. लक्ष्मण

'एक देश, एक राशन कार्ड' योजना बन रही गरीबों के लिए वरदान। मोदी सरकार ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 46.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। (16 दिसंबर, 2022)

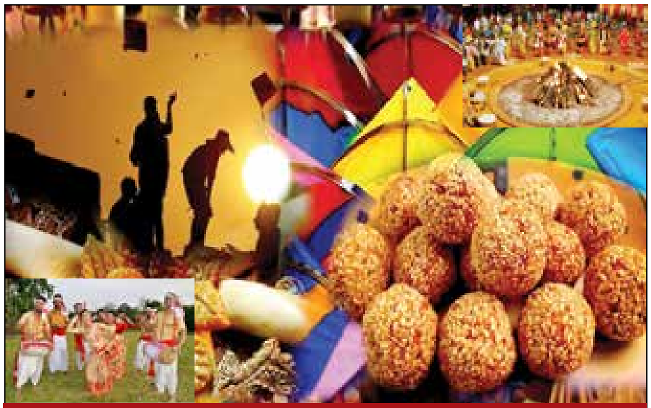

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
पोंगल, बिहु और मकर संक्रांति (14 जनवरी)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

परफॉरमेंस की राजनीति का युग

जब भाजपा गुजरात में पुनः सरकार बना रही थी एवं श्री भूपेन्द्र पटेल दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, भाजपा कार्यकर्ताओं के त्याग, समर्पण एवं तपस्या से एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। भाजपा जो पिछले 27 वर्षों से गुजरात में शासन में रही है और लगातार सातवीं बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल रही, परफॉर्मेंस की राजनीति के माध्यम से जनसेवा का व्रत इसके कार्यकर्ताओं का अब मंत्र बन चुका है। सुशासन एवं विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी राजनीति के फलस्वरूप उभरा 'गुजरात मॉडल' अब देश की राजनीति में एक प्रेरणा-पुंज बन चुका है। गुजरात के ऐतिहासिक जनादेश का संदेश स्पष्ट है कि अब देश में जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार एवं अवसरवाद की राजनीति को परफॉर्मेंस, प्रतिबद्धता एवं कड़ी मेहनत की राजनीति से हराया जा सकता है। कांग्रेस जो भ्रष्टाचार, वंशवाद, पॉलिसी पैरालिसिस एवं विभाजनकारी राजनीति की पर्याय बन चुकी है, अब देश की राजनीति के हाशिए पर है। जहां जनता के भारी आशीर्वाद से हर कार्यकर्ता का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हुआ है, वहीं अब हर कार्यकर्ता को पुनः जन-जन की सेवा में समर्पित होकर मां भारती को परम वैभव पर ले जाने की साधना करनी पड़ेगी।

> गुजरात के ऐतिहासिक जनादेश का संदेश स्पष्ट है कि अब देश में जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार एवं अवसरवाद की राजनीति को परफॉर्मेंस, प्रतिबद्धता एवं कड़ी मेहनत की राजनीति से हराया जा सकता है

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का निंदनीय बयान न केवल पूरी तरह से अस्वीकार्य है, बल्कि किसी भी सभ्य समाज द्वारा भर्त्सना योग्य भी है। यह निःसंदेह उस कुंठित मानसिकता का परिणाम है जिसमें आज पाकिस्तान पूरी तरह से डूबा हुआ है। पाकिस्तान का आतंकवाद को अंध-समर्थन, विभिन्न आतंकी गुटों एवं आतंकियों के साथ नापाक गठजोड़ तथा अंडरवर्ल्ड के साथ सांठ-गांठ जगजाहिर है। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद को पनाह देने, उसे प्रायोजित करने और बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। आतंकवाद के निर्यातक के रूप में पाकिस्तान विश्व के कई देशों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले दुर्दांत आतंकियों को अपनी जमीन पर हर प्रकार की सहायता देने के लिए कुख्यात है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत एवं दृढ़निश्चयी नेतृत्व में भारत आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण आज आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है तथा पाकिस्तान वैश्विक समुदाय के हाशिए पर पहुंच गया है। भारत के प्रधानमंत्री पर निंदनीय एवं शर्मनाक बयान पाकिस्तान पर वैश्विक समुदाय के बढ़ते दबाव का परिणाम है। आतंकवाद के पनाहगार के रूप में कुख्यात पाकिस्तान के मंत्री के बयान की कड़ी से कड़ी शब्दों में भर्त्सना हो रही है।

एक ओर जहां संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस ने तवांग पर आधारहीन प्रश्न उठाकर देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना पर दिया गया राहुल गांधी का बयान अत्यंत अशोभनीय एवं निंदनीय है। यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने भारतीय सेना की उपलब्धियों को छोटा करने का प्रयास किया तथा उनकी क्षमता के सामने प्रश्न खड़े किए। पूर्व में भी कई बार कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर ऐसी धृष्टता कर चुकी है। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम एवं साहस का सम्मान करने के स्थान पर कांग्रेस सेना का अपमान कर निरंतर देश का मनोबल तोड़ने का प्रयास करती रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के बयान अक्सर पाकिस्तान के बयानों से मिलते-जुलते हैं और कई बार चीन के पक्ष में दिखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस को तत्काल पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा भविष्य में इस प्रकार के आपराधिक कृत्य न हो।

एक बार फिर मोदी सरकार ने 'अंत्योदय' के सिद्धांतों के प्रति अपनी गहरी आस्था का परिचय दिया है। हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को अगले एक वर्ष तक मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसमें कोई संशय नहीं कि अंत्योदय पर अटूट आस्था से एक नए भारत का उदय होगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

गुजरात में 7वीं बार भाजपा सरकार

भूपेंद्र पटेल ने ली दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ

16 मंत्रियों ने भी ली शपथ

गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद 12 दिसंबर, 2022 को श्री भूपेंद्र पटेल ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड मैदान में एक भव्य समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सहित 16 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इसमें से आठ कैबिनेट मंत्री, दो राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं छह राज्य मंत्री हैं।

कैबिनेट मंत्रियों की सूची	
1.	श्री कनुभाई मोहनलाल देसाई
2.	श्री ऋषिकेश गणेशभाई पटेल
3.	श्री राघवजीभाई हंसराजभाई पटेल
4.	श्री बलवंतसिंह चंदनसिंह राजपूत
5.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया
6.	श्री मुलुभाई हरिदासभाई बेरा
7.	डॉ. कुबेरभाई मनसुखभाई डिंडोर
8.	श्रीमती भानुबेन मनोहरभाई बाबरिया

प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को शपथ लेने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री भूपेंद्रभाई पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "श्री भूपेंद्रभाई पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मंत्रियों के रूप में शपथ ली है। यह एक ऊर्जावान टीम है, जो गुजरात को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।"

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	
1.	श्री हर्ष रमेशकुमार सांघवी
2.	श्री जगदीश विश्वकर्मा

राज्य मंत्री	
1.	श्री पुरुषोत्तमभाई उद्धवजी भाई सोलंकी
2.	श्री बच्चूभाई मगनभाई खबाड
3.	श्री मुकेशभाई जीनाभाई पटेल
4.	श्री प्रफुल छगनभाई पंशेरिया
5.	श्री भीखूसिंहजी चतुरसिंहजी परमार
6.	श्री कुंवरजीभाई नरसिंहभाई हलपति

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे।

इसके साथ ही भाजपा एवं राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रीगण— योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), श्री शिवराज सिंह चौहान (मध्य प्रदेश), श्री बसवराज बोम्मई (कर्नाटक), श्री हिमंत बिस्वा सरमा (असम), श्री मनोहर लाल खट्टर (हरियाणा), डॉ. प्रमोद सावंत (गोवा), श्री पुष्कर सिंह धामी (उत्तराखंड), श्री माणिक साहा (त्रिपुरा), श्री नेफियू रियो (नागालैंड), श्री एकनाथ शिंदे (महाराष्ट्र) एवं श्री देवेंद्र फडणवीस (उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र) शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे।

नए मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को जगह मिली है, उनमें से 11 पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। विदित हो कि गुजरात में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। यहां 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को दो चरणों में मतदान हुए थे। 8 दिसंबर को घोषित हुए नतीजों में भाजपा ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 156 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। 17 सीटें कांग्रेस को और 5 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थीं।

गुजरात प्रगति व समृद्धि का स्वर्णिम अध्याय लिखेगाः जगत प्रकाश नड्डा

शपथ ग्रहण समारोह के बाद श्री भूपेंद्र पटेल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई देते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, “श्री भूपेंद्र पटेल जी को पुनः गुजरात के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश प्रगति व समृद्धि का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा।”

श्री नड्डा ने आगे ट्वीट कर कहा, “आज (21 दिसंबर) गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से भेंटकर उन्हें सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास के शिखर पर पहुंचेगा।”

हर वर्ग के कल्याण के प्रति पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से कार्य करें : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, "श्री भूपेंद्र पटेल को पुनः गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर बधाई। गुजरात की जनता ने भाजपा की विकास की राजनीति को अभूतपूर्व समर्थन दिया है। मुझे विश्वास है कि नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भूपेन्द्र जी की डबल इंजन सरकार गुजरात के गौरव व विकास को नए शिखर पर ले जाएगी।"

उन्होंने कहा, "गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से भेंट हुई। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में गुजरात सरकार प्रदेश को प्रगति के नए शिखर पर ले जाएगी।"

एक सफल आगामी कार्यकाल की शुभकामनाएं : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ट्वीट कर कहा, "दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए श्री भूपेंद्र पटेल जी को बधाई। मैं आश्वस्त हूं, वह राज्य को विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों तक आगे ले जाना जारी रखेंगे। एक सफल आगामी कार्यकाल की शुभकामनाएं।"

उन्होंने आगे कहा, "गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की। एक सफल आगामी कार्यकाल हेतु उन्हें मेरी शुभकामनाएं।"

भूपेंद्र पटेल चुने गए विधायक दल के नेता

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने 10 दिसंबर, 2022 को श्री भूपेंद्र पटेल को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय 'कमलम' में हुई बैठक में श्री पटेल को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता घोषित किया गया। श्री पटेल ने 9 दिसंबर को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राज्य में नई सरकार के गठन से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था।

'कमलम' में नवनिर्वाचित 156 विधायकों की बैठक हुई, जहां विधायक श्री कनु देसाई ने विधायक दल के नेता के रूप में श्री भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा संसदीय दल के सदस्य श्री बी.एस. येदियुरप्पा एवं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उपमुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल एवं पूर्व शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र चूडासामा भी उपस्थित थे।

> "भाजपा ने संकल्प पत्र में जिन मुद्दों को शामिल किया है, उन तमाम मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के लोगों ने भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर जो भरोसा किया है, उसे हम टूटने नहीं देंगे"

इस अवसर पर श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में जिन मुद्दों को शामिल किया है, उन तमाम मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के लोगों ने भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर जो भरोसा किया है, उसे हम टूटने नहीं देंगे। ■

भूपेंद्र रजनीकांत पटेल

जीवन परिचय

श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने 12 दिसंबर, 2022 को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कुल 182 सीटों में से 156 सीटों पर रिकॉर्ड जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही प्रदेश में लगातार 7वीं बार भाजपा सरकार बनी है।

श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने मेमनगर नगरपालिका के सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी और 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र (अहमदाबाद) से विधायक चुने गए।

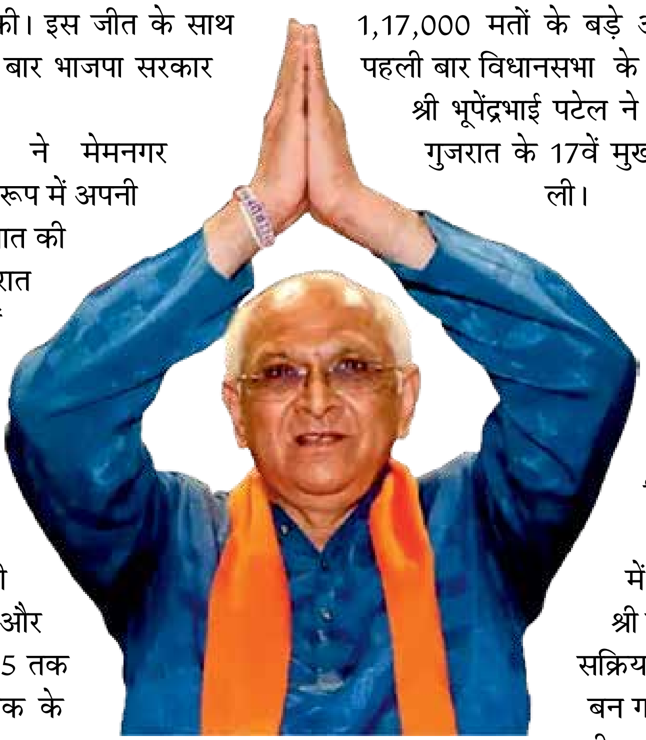

श्री पटेल अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे और उन्होंने वर्ष 2010 से 2015 तक थलतेज वार्ड के नगरसेवक के रूप अपने दायित्व को निभाया। श्री पटेल के पास एक व्यापक प्रशासनिक अनुभव है।

उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1995 में की, जब उन्हें मेमनगर नगरपालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक नगरपालिका में अपनी सेवाएं दी, वह 1999-2000 और 2004-2006 के दौरान स्थानीय निकाय के अध्यक्ष रहे।

उन्होंने 2008 और 2010 के बीच अहमदाबाद नगर निगम स्कूल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। बाद में, वे 2010 से 2015 तक पार्षद रहे। अपने इस कार्यकाल के दौरान श्री पटेल अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे।

2015 में उन्हें अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

2017 में श्री पटेल घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र से 1,17,000 मतों के बड़े अंतर से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा के सदस्य बने।

श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने 13 सितंबर, 2021 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

15 जुलाई, 1962 को अहमदाबाद में जन्मे श्री पटेल के पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है।

'स्वयं से पहले सेवा' में दृढ़ विश्वास रखने वाले श्री पटेल कम उम्र से ही एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता बन गये थे। वे मेमनगर पंडित दीनदयाल पुस्तकालय के सक्रिय सदस्य भी रहे।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी नई भूमिका में श्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के नागरिकों की सेवा करने का एक बड़ा अवसर देखते हैं और वह प्रदेश में सुशासन के नए मानदंड स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री पटेल को बैडमिंटन और क्रिकेट खेलना पसंद है। वे दादा भगवान द्वारा स्थापित अक्रम विज्ञान आंदोलन के अनुयायी रहे। श्री पटेल सरदार धाम और विश्व उमिया फाउंडेशन में ट्रस्टी के रूप में अपने दायित्व को निभा रहे हैं।

गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मा. श्री भूपेंद्र पटेल जी व साथी मंत्रीगणों को हार्दिक बधाई! माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आप लोक कल्याण, गरीब उत्थान के संकल्प को साकार करते हुए विकास के नए प्रतिमान स्थापित करें, यही शुभकामनाएं देता हूं।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री भूपेंद्र पटेल जी को बधाई! जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं भाजपा में आस्था दिखाते हुए जो ऐतिहासिक जनादेश दिया है, वह गुजरात को दीर्घकालिक विकास एवं समृद्धि के पथ पर अग्रसर करेगा।

मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री, हरियाणा

श्री भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। यह जनसेवा के प्रति आपके समर्पण की पुष्टि है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आप गुजरात को विकास के पथ पर और आगे ले जाएंगे।

हिमंत बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री, असम

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री भूपेंद्र पटेल जी को अनंत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में डबल इंजन सरकार, गुजरात को दोगुनी गति से विकासपथ पर अग्रसर करेगी, आजादी के अमृतकाल में गुजरात से बह रही विकास की बयार सम्पूर्ण राष्ट्र में अबाध बहेगी।

प्रो. (डॉ.) माणिक साहा, मुख्यमंत्री, त्रिपुरा

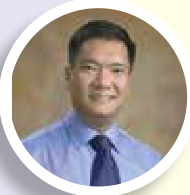

श्री भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई! जैसा कि आप दूसरे कार्यकाल के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश गौरव प्राप्त करेगा और समृद्धि बनेगा। शुभकामनाएं!

पेमा खांडू, मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश

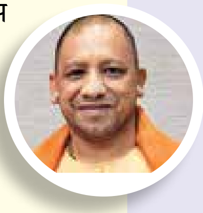

श्री भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ लेने पर हार्दिक बधाई! पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प की पूर्णता में महत्वपूर्ण सहयोगी सिद्ध होगा।

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

श्री भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ लेने एवं उनके समस्त नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन व आपके ऊर्जावान नेतृत्व में गुजरात विकास के पथ पर अविराम गतिशील रहेगा। आप सभी को उज्ज्वल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

श्री भूपेंद्र पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई, यह मुख्यमंत्री के रूप में आपका दूसरा कार्यकाल है और प्रदेश की सत्ता में एक दल के रूप में भाजपा का सातवां कार्यकाल है। यह उनके सुशासन और प्रशासन में गुजरात के लोगों के विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है।

बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री, कर्नाटक

गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुआ। श्री भूपेंद्र पटेल जी और आज शपथ लेने वाले मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हार्दिक बधाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली। मैं आपके और मंत्रिपरिषद के सफल कार्यकाल की कामना करता हूं।

नेफियू रियो, मुख्यमंत्री, नागालैंड

भाजपा 'सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं' की नीति में विश्वास रखती है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 15 दिसंबर, 2022 को कवालुरु (कोप्पल), कर्नाटक में कोप्पल जिला कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ-साथ कर्नाटक के 9 अन्य जिला कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन और तीन जिला कार्यालयों का वर्चुअली शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री नलिन कटील, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा संसदीय दल के सदस्य श्री बी.एस. येदियुरप्पा एवं कर्नाटक के प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्रीगण, भाजपा के सांसदगण, विधायकगण तथा जिला पदाधिकारीगण उपस्थित थे। साथ ही, 9 अन्य जिला कार्यालयों से जिला पदाधिकारी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पार्टी कार्यकर्ता भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े थे।

श्री नड्डा ने कहा कि आज कर्नाटक भाजपा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रदेश में एक साथ भाजपा के 10 जिला कार्यालयों का उद्घाटन और तीन जिला कार्यालयों का शिलान्यास हो रहा है। अब तक पार्टी के लगभग 296 जिला कार्यालय बन चुके हैं और 210 अन्य जिला कार्यालय मार्च, 2023 तक पूरे हो जायेंगे।

देश की एकता और अखंडता के लिए भाजपा की सक्रियता

श्री नड्डा ने कहा कि यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्र के विषयों पर देशभक्ति से ओतप्रोत होकर जनसंघ के समय से ही अनवरत रूप से काम कर रही है। चाहे धारा 370 का उन्मूलन हो, जम्मू-कश्मीर में पूज्य डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हो, गोवा मुक्ति आंदोलन हो या कश्मीर घाटी में लाल चौक पर तिरंगा फहराना हो, देश की एकता और अखंडता से जुड़े हर काम में भाजपा ने आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। हम 'Appeasement to none but Justice to all' की नीति में विश्वास रखते हैं। मतलब, न्याय सबको मिलेगा लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। अगर शाहबानो केस में ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को ख़त्म करने की किसी ने वकालत की तो भाजपा ने की और अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि बनाने का संकल्प भी लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया।

भाजपा सरकार में कर्नाटक का विकास

केंद्र की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वरा कर्नाटक के विकास के लिए किये गए कार्यों को विस्तार से रेखांकित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी 11 नवंबर को ही कर्नाटक आये थे और उन्होंने कर्नाटक को 'वंदे भारत' की सौगात दी थी। ऐसी लगभग 400 ट्रेनें शुरू होने वाली है। कर्नाटक से काशी और अयोध्या की यात्रा के लिए भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन शुरू हुई। कैम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सरकार द्वारा लगभग 5,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। न्यू मैंगलोर पोर्ट बना है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में महिलाओं के सम्मान, उनकी सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण के लिए जितना येदियुरप्पाजी और बोम्मईजी ने किया है, उतना किसी ने भी नहीं किया है। 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत कर्नाटक में लाखों घरों में शौचालय बनाए गए, 'आयुष्मान भारत' के साथ-साथ प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी राज्य के हर गरीब नागरिक के लिए मुफ्त हेल्थ कवर उपलब्ध कराया और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। उजाला योजना के तहत कर्नाटक में लगभग ढाई करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये गए और उज्ज्वला योजना के तहत कर्नाटक में लगभग 33 लाख बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया।

शेष पृष्ठ 13 पर...

प्रजा संग्राम यात्रा, करीमनगर (तेलंगाना)

'टीआरएस सरकार प्रजातंत्र का गला घोंटने वाली और जन विरोधी सरकार है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 15 दिसंबर, 2022 को करीमनगर (तेलंगाना) के एसआरआर डिग्री कॉलेज ग्राउंड में भाजपा के राज्यव्यापी प्रजा संग्राम यात्रा के समापन समारोह के अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और तेलंगाना की जनता से राज्य की भ्रष्टाचारी केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कार्यक्रम को तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष श्री बांदी संजय कुमार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ, भाजपा विधायक श्री एटला राजेन्द्र, श्री पी. मुरलीधर राव, सांसद श्री अरविंद धर्मपुरी और सह-प्रभारी श्री अरविंद मेनन सहित तेलंगाना भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

'प्रजा गोसा, बीजेपी भरोसा'

श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंदी संजय कुमार जी के नेतृत्व में तेलंगाना में पांच चरणों में राज्यव्यापी 'प्रजा संग्राम यात्रा' आज पूरी हुई है। इस दौरान 114 दिनों की पदयात्रा हुई जो तेलंगाना की 56 विधान सभाओं से होकर गुजरी है और लगभग 1458 किलोमीटर की दूरी तय की गई। आज प्रजा संग्राम यात्रा का समापन नहीं हुआ है, बल्कि पदयात्रा का एक फेज पूरा हुआ है। भाजपा अगली यात्रा की घोषणा जल्द ही करेगी, तेलंगाना के गांव-गांव, घर-घर जायेगी और केसीआर सरकार की पोल खोलेगी। यह यात्रा रुकने वाली नहीं है, यह तो तेलंगाना की जनता की आवाज बनने की शुरुआत है। अब हमने एक नया अभियान 'प्रजा गोसा, बीजेपी भरोसा' शुरू किया है। इसके माध्यम से हम तेलंगाना के गांव-गांव, घर-घर जायेंगे जिसमें हमारे सभी नेता शामिल होंगे। भाजपा ने एक नया नारा दिया है— "सालु डोरा—सेलावु डोरा" मतलब enough is enough, goodbye KCR. प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे और तीसरे चरण के दौरान मेरी यात्रा को भी रोकने का काम तेलंगाना की टीआरएस सरकार के लोगों ने किया था। मैं केसीआर को बता देना चाहता हूं और उन्हें याद रहना चाहिए कि ये प्रजातंत्र है और दमनकारी ताकतों को लोकतंत्र में जनता कूड़ेदान में दफ़न कर दिया करती है। भाजपा ने बांदी संजय कुमार के नेतृत्व में 'प्रजा संग्राम यात्रा' को निकाल कर टीआरएस सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश को उजागर किया है।

भ्रष्टाचार और अनाचार में डूबी केसीआर सरकार

श्री नड्डा ने कहा कि आज देश में एक ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की नीति के साथ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी कल्याण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़ों, युवा एवं महिलाओं को ताकत दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना में केसीआर की सरकार है जो भ्रष्टाचार और अनाचार में डूबी हुई है। साथ ही, यह टीआरएस सरकार प्रजातंत्र का गला घोंटने वाली और जन विरोधी सरकार है। ऐसी सरकार को सत्ता में न बने रहने का हक़ है और न ही जनता को धोखा देने का हक़ है। अब समय आ गया है उन्हें गुडबाय करने का। तेलंगाना की जनता ऐसे लोगों को आराम दे और हमें सेवा का अवसर दे।

कर्ज के बोझ तले दबा तेलंगाना

तेलंगाना की केसीआर सरकार पर जोरदार हमला करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आज से 8 साल पहले तेलंगाना एक सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज तेलंगाना को कर्ज के बोझ तले दबाकर अंधेरे में धकेलने का काम केसीआर में किया है। आज तेलंगाना लगभग 3.29 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है। केसीआर कहते हैं कि तेलंगाना रिचेस्ट स्टेट है। मैं केसीआर को correct करना चाहता हूं कि Telangana was a richest state but you have made it a poor and debt state. तेलंगाना की एक स्थानीय कहावत को तेलुगु में बोलते हुए श्री नड्डा ने कहा कि 'छत पर हांडी टांगने की जगह नहीं और सपने आसमान के' - इस तरह के सपने केसीआर देख रहे हैं। ये कभी भी तेलंगाना का भला नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है,

केसीआर को गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन आखिर जांच एजेंसी को केसीआर की बेटी को पूछताछ के लिए बुलाना क्यों पड़ा? ये कैसी विडंबना है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई टीआरएस (TRS - Telangana Rashtra Samithi) अब पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस (BRS - Bharat Rashtra Samithi) कर रही है लेकिन जल्द ही वे अपनी पार्टी का नाम BRS से VRS (Voluntary Retirement Scheme) करने वाले हैं। दुब्बका और हुजूराबाद में भाजपा की शानदार जीत ने तेलंगाना की जनता के इरादे जता दिए हैं कि आने वाले विधान सभा चुनाव में तेलंगाना की जनता भाजपा को ही चुनेगी।

जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहे मंत्री और विधायक

श्री नड्डा ने कहा कि एक समय केसीआर कहते थे कि प्रजातांत्रिक तरीके से तेलंगाना में सरकार चलाएंगे, दलित को मुख्यमंत्री बनायेंगे लेकिन अब केसीआर को बेटा-बेटी और दामाद के सिवा कोई और दिखता ही नहीं है। लोकतंत्र की बात करने वाला व्यक्ति आज परिवारवाद को फैलाने में जुटा है। तेलंगाना में मैक्रो लेवल पर लूट का काम केसीआर के संरक्षण में चल रहा है। छोटे स्तर पर इनके मंत्री और विधायक जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने में लगे हैं। इन्होंने न केवल जनता को धोखा दिया है, बल्कि उन लोगों के साथ भी विश्वासघात किया है, जिन्होंने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने में अपने-आप को आहूत कर दिया।

केसीआर नहीं चाहते कि 'लिबरेशन डे' मने

श्री नड्डा ने कहा कि 17 सितंबर को इस बार से हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 'लिबरेशन डे' मनाने की शुरुआत की है। हम 'लिबरेशन डे' को और जोर-शोर से मनाएंगे। केसीआर नहीं चाहते कि 'लिबरेशन डे' मने, क्योंकि उन्हें ओवैसी से संबंध रखना है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना का इतिहास भी जानती है, रजाकारों की क्रूरता भी जानती है और यह भी कि किस तरह रजाकारों ने तेलंगाना में समाज को बांटने का कुप्रयास किया। हम यह भी जानते हैं कि किस तरह भारत की जनता ने रजाकारों का मुकाबला किया और देश की आजादी में अपने-आप को जोड़ा।

केसीआर की वादाखिलाफी

श्री नड्डा ने कहा कि केसीआर ने वादा किया था कि गरीबों को टू-बेडरूम बनाकर देंगे। केसीआर ने अपना तो फ़ार्म हाउस बना लिया, लेकिन गरीबों से उनका घर भी छीन लिया। केसीआर ने वादा किया था कि किसानों का एक बार कृषि लोन भी माफ़ करूंगा, लेकिन तेलंगाना के किसान आज तक कर्ज माफी के इंतजार में हैं। केसीआर ने यह भी वादा किया था कि प्रत्येक एससी को दो एकड़ और प्रत्येक एसटी को तीन एकड़ जमीन देंगे, लेकिन आज तक यह वादा भी पूरा नहीं हुआ। केसीआर ने राज्य के युवाओं को 3,016 रुपये हर महीने stipend के रूप में देने का वादा किया था, लेकिन आज तक युवा 3,016 रुपये के इंतजार में हैं। मुझे तो आज तक यह समझ में नहीं आया कि ये 16 रुपये क्यों जोड़े गए थे? केसीआर ने केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई का भी वादा किया था, लेकिन वह वादा भी पूरा नहीं हुआ।

टीआरएस सरकार को सत्ता से केवल भाजपा ही हटा सकती है

श्री नड्डा ने तेलंगाना की जनता से अपील करते हुए कहा कि जो लोग चाहते हैं कि केसीआर की सरकार जाए, टीआरएस की भ्रष्टाचारी, दमनकारी और कुशासन वाली सरकार जाए तो उन्हें ये याद रखना पड़ेगा कि टीआरएस सरकार को कोई सत्ता से यदि हटा सकता है तो वह केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है। जो भी लोग टीआरएस की सरकार और उसके कुशासन, भ्रष्टाचार तथा केसीआर के वंशवाद और भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, मैं उनका आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब भाजपा के साथ जुड़िये, भाजपा के हाथ मजबूत कीजिये और तेलंगाना में कमल खिलाइए। ■

पृष्ठ 11 का शेष...

'भारत जोड़ो' यात्रा नहीं बल्कि 'भारत तोड़ो' यात्रा

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी तथाकथित 'भारत जोड़ो' यात्रा पर कर्नाटक आये थे। वास्तव में यह 'भारत जोड़ो' यात्रा नहीं बल्कि 'भारत तोड़ो' यात्रा है। राहुल गांधी प्रायश्चित यात्रा पर हैं क्योंकि इनके पूर्वजों ने भारत को तोड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी को क्या यह मालूम नहीं है कि उनके परनाना ने धारा 370 को लागू कर जम्मू-कश्मीर को एक तरह से देश से अलग करने का प्रयास नहीं किया था? ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने वालों का समर्थन किया था। ऐसे लोग भारत जो जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? राहुल गांधी 'भारत जोड़ो' यात्रा में ऐसे कई लोगों को साथ लेकर घूम रहे हैं जो देश की एकता और भारतीय संस्कृति की विरासत में यकीन नहीं रखते। ये देश को जोड़ने नहीं, तोड़ने चले हैं।

भाजपा कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को कर्नाटक के घर-घर जाना है और उन्हें इस बात से अवगत कराना है कि किस तरह से भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया है। ■

पाकिस्तानी मंत्री की टिप्पणी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी ने 17 दिसंबर, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की निंदा करते हुए एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। भुट्टो के इस बयान को लेकर पूरे देश में नाराजगी देखी गई, उन्होंने यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिहार, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना और राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भुट्टो की टिप्पणी की निंदा करते हुए एक विरोध मार्च निकाला।

उत्तर प्रदेश में भुट्टो की टिप्पणी के खिलाफ आंदोलन 16 दिसंबर से ही शुरू हो गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने एक बयान जारी कर श्री मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणी को शर्मनाक बताया। कार्यकर्ताओं ने लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, महोबा और प्रयागराज सहित विभिन्न जिलों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में पुणे में भाजपा नेताओं ने तिलक चौक पर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने मुंबई और प्रदेश के अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन किया।

गुजरात में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।

कर्नाटक और तेलंगाना में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकालीं और बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और बिना शर्त माफी की मांग की।

भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ओडिशा असम, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन किया।

पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है: एस. जयशंकर

विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने भी आतंकवाद को प्रायोजित करने और फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर उसकी आलोचना की और इस्लामाबाद को सलाह दी कि वह अपनी हरकतों से बाज आए और एक अच्छा पड़ोसी बनने का प्रयास करे। भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाने वाले एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में श्री जयशंकर ने कहा, 'आप गलत मंत्री से पूछ रहे हैं कि हम ऐसा कब तक

करेंगे। आपको पाकिस्तान के मंत्री ही बताएंगे कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद को फैलाने का इरादा रखता है।”

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भी भुट्टो की टिप्पणी को बौद्धिक दिवालियापन के संकेत के तौर पर परिभाषित करते हुए उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी सत्ता में बने रहने, दुनिया को गुमराह करने और पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था से वैश्विक ध्यान हटाने और पाकिस्तानी सेना में बढ़ते मतभेदों, बिगड़ते वैश्विक संबंधों और पाकिस्तान प्रायोजित आंतकवाद को छिपाने का प्रयास है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, यह बयान उनकी और उनकी सरकार की हताशा एवं मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। ■

यह टिप्पणी 'बेहद अपमानजनक और कायरतापूर्ण है' : भाजपा

एक आधिकारिक बयान में भाजपा ने कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री के शर्मनाक बयान की निंदा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रदेशों में बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान का पुतला फूंका। भुट्टो की टिप्पणियों की निंदा करते हुए भाजपा ने कहा कि इस निंदनीय और अनुचित टिप्पणियों ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की छवि को और कम किया है। पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके छात्रों को भारतीय तिरंगे की सुरक्षा में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से निकाला गया था।

बयान में कहा गया कि टिप्पणी 'अत्यधिक अपमानजनक और कायरतापूर्ण' है और इस बयान का उद्देश्य सत्ता में बने रहने, दुनिया को गुमराह करने और पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था से वैश्विक ध्यान हटाने और पाकिस्तानी सेना में बढ़ते मतभेदों, बिगड़ते वैश्विक संबंधों और पाकिस्तान प्रायोजित आंतकवाद को छिपाने का प्रयास है।

भाजपा ने कहा कि भारत की विदेश नीति की विश्व स्तर पर सराहना की जा रही है, जबकि पाकिस्तान को छोटे देशों से भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। “एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जिनके नेतृत्व में भारत ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और दूसरी तरफ, पाकिस्तान है जिसने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उपहास और अपमान का सामना किया है। एक ओर, भारत की विदेश नीति की विश्व स्तर पर सराहना हो रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को छोटे देशों से भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

भाजयुमो ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया

भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बिलावल के बयान के खिलाफ 16 दिसंबर को नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर धरना दिया। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या ने कहा भाजयुमो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के उस बयान की कड़ी निंदा करती है, जिसमें प्रधानमंत्री को श्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी है। जिस देश का एकमात्र निर्यात आतंकवाद है उससे इससे बेहतर कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती है।

श्री सूर्या ने आगे कहा, “बिलावल भुट्टो असफल पाकिस्तान राज्य के कुंठित राजनीतिक वंश से आते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी की आतंक के खिलाफ वैश्विक जंग से पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर नुकसान हो रहा है और स्वाभाविक रूप से आईएसआई नियंत्रित विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री श्री मोदी के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक बयान दे रहे हैं। भारत इसकी निंदा करता है।”

भाजयुमो को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भद्दी और द्वेषपूर्ण टिप्पणियों की निंदा करने के लिए साथी भारतीयों और दुनिया भर के लोगों से संदेश प्राप्त हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र में 16 दिसंबर, 2022 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की गई असभ्य टिप्पणी की भाजयुमो कड़ी निंदा करती है। यह टिप्पणियां पाकिस्तान की विफल स्थिति में खुद को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे एक हताश राजनीतिक राजवंश की हताशा को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी को लेकर दिया गया बयान एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से ध्यान हटाने की उनकी हताशा को भी दिखाता है।

भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की उक्त टिप्पणी के खिलाफ देशभर के सभी प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन किया। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया ने पाकिस्तान के इस बयान को लेकर उसकी निंदा की है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। ■

ऐतिहासिक निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 81.35 करोड़ लाभार्थी को दिसंबर, 2023 तक नि:शुल्क अनाज देने की दी मंजूरी

केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर, 2022 को इस फैसले को मंजूरी दी।

देश के गरीबों का कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसे में उनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसका सीधा लाभ देश के लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा।

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

दिसंबर, 2023 तक 81.3 करोड़ गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नि:शुल्क राशन प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऐतिहासिक फैसले से खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और वंचितों को राहत मिलेगी।

- जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेएवाई) की शुरुआत अप्रैल, 2020 में ऐसे गरीब परिवारों की मदद के लिए की गई थी, जिनकी आजीविका कोरोना महामारी को प्रसार से रोकने हेतु लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई थी। महामारी के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 28 माह तक 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 5 किलो खाद्यन्न नि:शुल्क दिया गया। यह योजना 28 महीने से लागू है। इसका नवीनतम विस्तार इसी महीने समाप्त हो रहा था। पिछले 28 महीनों में सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत गरीबों को नि:शुल्क राशन वितरण पर 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सितंबर, 2022 में केंद्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई को तीन महीने के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि

केंद्र इस अवधि में एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगा, जिससे गरीबों के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।

श्री गोयल ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है, जो कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु:

- एनएफएसए व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी पर केंद्र अगले एक साल में दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा
- प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों (गरीब से गरीब) को 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार अगले एक साल तक मुफ्त प्रदान किया जाएगा
- एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को रियायती दर पर तीन रुपये प्रति किलो चावल, दो रुपये प्रति किलो गेहूं और एक रुपये प्रति किलो मोटे अनाज का वितरण किया गया है
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज मिलेगा ■

'वन रैंक वन पेंशन' में पुनरीक्षण, 25.13 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

इसके तहत 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिक कवर किए जायेंगे और जुलाई, 2019 से लेकर जून, 2022 तक के बकाये के रूप में 23,638 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर को 'वन रैंक, वन पेंशन' (ओआरओपी) के तहत सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में पुनरीक्षण को 01 जुलाई, 2019 से मंजूरी दे दी। पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी।

30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिकों {01 जुलाई, 2014 से समय-पूर्व (पीएमआर) सेवानिवृत्त होने वाले को छोड़कर} को इस पुनरीक्षण के तहत कवर किया जाएगा। 25.13 लाख से अधिक (4.52 लाख से अधिक नए लाभार्थियों सहित) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। निर्धारित औसत से अधिक पेंशन पाने वालों की पेंशन को संरक्षित किया जाएगा। यह लाभ युद्ध में शहीद होने वाले सैन्यकर्मियों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा।

बकाये का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा। हालांकि, विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक किस्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

पुनरीक्षण के कार्यान्वयन से 8,450 करोड़ रुपये @ 31 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) का अनुमानित वार्षिक व्यय होगा। 01 जुलाई, 2019 से लेकर 31 दिसंबर, 2021 तक के बकाये की गणना 01 जुलाई, 2019 से लेकर 30 जून, 2021 की अवधि के लिए डीआर @ 17 प्रतिशत और 01 जुलाई, 2021 से लेकर 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के लिए @ 31 प्रतिशत के आधार पर की गई है और यह राशि 19,316 करोड़ रुपये से अधिक है।

01 जुलाई, 2019 से लेकर 30 जून, 2022 तक कुल बकाया राशि लागू महंगाई राहत के अनुसार लगभग 23,638 करोड़ रुपये की होगी। यह व्यय ओआरओपी के मद में हो रहे व्यय के अतिरिक्त है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने रक्षा बलों के कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' (ओआरओपी) को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और 01 जुलाई, 2014 से पेंशन में पुनरीक्षण के लिए 07 नवंबर, 2015 को नीति पत्र जारी किया। उक्त नीति पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि भविष्य में पेंशन हर पांच वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी। ओआरओपी के कार्यान्वयन में आठ वर्षों में प्रति वर्ष 7,123 करोड़ रुपये की दर से लगभग 57,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ■

भारत वैज्ञानिक प्रकाशनों की वैश्विक श्रेणी में 7वें स्थान से छलांग लगाकर अब तीसरे स्थान पर

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 18 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशनों की वैश्विक श्रेणी में 7वें स्थान से छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में 7वें स्थान से सुधरकर 2020 में तीसरे स्थान पर आ गई है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत के विद्वानों का कार्य 2010 में 60,555 शोध प्रपत्रों (पेपर्स) से बढ़कर 2020 में 1,49,213 शोध प्रपत्र (पेपर) हो गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर गर्व किया कि भारत अब विज्ञान और इंजीनियरिंग में शोध (पीएचडी) की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। उन्हें इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) में भारतीय वैज्ञानिकों को दिए गए पेटेंट की संख्या भी 2018-19 के 2511 से बढ़कर 2019-20 में 4003 और 2020-21 में 5629 हो गई है। उल्लेखनीय है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा लाए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स – जीआईआई) 2022 के अनुसार भारत की जीआईआई श्रेणी में भी 2014 के 81वें स्थान से 2022 में 40वें स्थान पर पहुंचने का महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ■

वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में 25.90 प्रतिशत की हुई वृद्धि

वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह 19.81 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा और अग्रिम कर संग्रह 5,21,302 करोड़ रुपये का हुआ, जो 12.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 17 दिसंबर, 2022 तक प्रत्यक्ष करों के संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह 11,35,754 करोड़ रुपये का हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि में शुद्ध संग्रह 9,47,959 करोड़ रुपये का हुआ था, जो 19.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

11,35,754 करोड़ रुपये (17 दिसंबर, 2022 तक) के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 6,06,679 करोड़ रुपये (रिफंड के बाद) का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) और 5,26,477 करोड़ रुपये (रिफंड के बाद) का प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है।

वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह (रिफंड के समायोजन से पहले) पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 10,83,150 करोड़ रुपये की तुलना में 13,63,649 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि में हुए सकल संग्रह की तुलना में 25.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

13,63,649 करोड़ रुपये के सकल संग्रह में 7,25,036 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) और 6,35,920 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है।

'छोटे मद' वार संग्रह में 5,21,302 करोड़ रुपये का अग्रिम कर; 6,44,761 करोड़ रुपये का टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती); 1,40,105 करोड़ रुपये का स्व-आकलन कर; 46,244 करोड़ रुपये का नियमित आकलन कर और अन्य छोटे मदों के अंतर्गत आने वाला 11,237 करोड़ रुपये का कर शामिल है।

वित्त वर्ष 2022-23 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में अग्रिम कर का कुल संग्रह 17 दिसंबर, 2022 तक 5,21,302 करोड़ रुपये का हुआ, जबकि इससे ठीक पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 की इसी अवधि में 4,62,038 करोड़ रुपये का अग्रिम कर संग्रह हुआ था, जो 12.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 17 दिसंबर, 2022 तक हुए 5,21,302 करोड़ रुपये के अग्रिम कर संग्रह में 3,97,364 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) और 1,23,936 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग की गति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और विधिवत रूप से सत्यापित आईटीआर का लगभग 96.5 प्रतिशत 17 दिसंबर, 2022 तक प्रोसेस किया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप रिफंड जारी करने में काफी तेजी आई है।

चालू वित्त वर्ष में जारी किए गए रिफंड की संख्या में लगभग 109 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2022-23 में 17 दिसंबर, 2022 तक 2,27,896 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि के दौरान 1,35,191 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया था, जो कि 68.57 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि दर्शाता है। ■

'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' के तहत नागरिकों के 4 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड किए गए डिजिटाइज़

नागरिक अपने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को कभी भी, कहीं भी एक्सेस और प्रबंधित कर सकते हैं और 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' के तहत कागज रहित डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं

भारत सरकार की प्रमुख स्कीम 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (एबीडीएम) देश के लिए व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के निर्माण में लगातार प्रगति हासिल कर रही है। व्यक्तियों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों से जुड़े 4 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ इस स्कीम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित कर ली है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 17 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अब तक 29 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अपने विशिष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) जेनरेट किए।

डिजिटल रूप से उनके एबीएचए खातों से जुड़े उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार इन रिकॉर्डों तक पहुंच और प्रबंधन कर सकेंगे। यह नागरिकों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में एक व्यापक चिकित्सा इतिहास का सृजन करने में सक्षम बनाता है, जिससे नैदानिक निर्णय लेने में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त, नागरिक एबीडीएम पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ डिजिटल रूप से संगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी साझा कर सकते हैं। ■

नौसेना को मिला स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत 'आईएनएस मोरमुगाओ'

'आईएनएस मोरमुगाओ' सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित युद्धपोतों में से एक है, जो देश की समुद्री क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करेगा

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर पी15बी वर्ग के दूसरे युद्धपोत भारतीय नौसेना जहाज (आईएनएस) मोरमुगाओ (डी67) को 18 दिसम्बर, 2022 को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। समारोह के दौरान भारतीय नौसेना के संस्थानिक संगठन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए और मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा निर्मित चार 'विशाखापत्तनम' श्रेणी के विध्वंसक में से दूसरे का औपचारिक रूप से समावेशन किया गया।

रक्षा मंत्री ने 'आईएनएस मोरमुगाओ' को सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित युद्धपोतों में से एक बताया, जो देश की समुद्री क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि आईएनएस मोरमुगाओ विश्व के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत मिसाइल वाहकों में से एक है। 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ यह युद्धपोतों के डिजाइन और विकास में भारत की उत्कृष्टता और हमारी बढ़ती स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं का एक बेहतरीन उदाहरण है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि यह युद्धपोत हमारे देश के साथ-साथ विश्व भर में हमारे मित्र देशों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। रक्षा मंत्री ने पूरे देश की ओर से भारतीय नौसेना को न केवल समुद्री हितों की रक्षा करने, बल्कि सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से बढ़ते व्यापार से जुड़ी है, जिनमें से अधिकांश समुद्री मार्गों के माध्यम से है। हमारे हित सीधे तौर पर हिंद महासागर से जुड़े हैं। इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश होने के कारण इसकी सुरक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ■

रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने सेनाओं के लिए 84,328 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी

खरीद प्रस्तावों में फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, हल्के टैंक, नौसेना पोत-रोधी मिसाइल, बहुउपयोगी पोत, मिसाइल प्रणाली की नई रेंज, लंबी दूरी के निर्देशित बम और अगली पीढ़ी के अपतटीय पेट्रोल पोत शामिल हैं

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) ने 22 दिसंबर को आयोजित बैठक में 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को मंजूरी दी। कुल 84,328 करोड़ रुपये के इन प्रस्तावों में भारतीय सेना के लिए छह, भारतीय वायु सेना के लिए छह, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए दो प्रस्ताव शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि इनमें स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए 82,127 करोड़ रुपये (97.4 फीसदी) के 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डीएसी की यह अद्वितीय पहल न केवल सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा उद्योग को भी पर्याप्त बढ़ावा देगी।

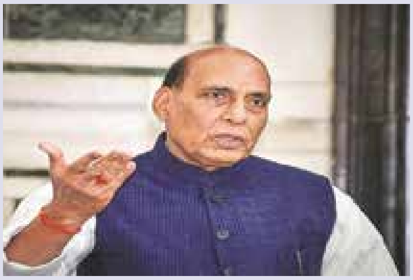

इस एएनओ को मंजूरी प्रदान किए जाने से भारतीय सेना परिचालन तैयारियों के लिए परिवर्तनकारी मंचों और उपकरणों जैसेकि— फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, हल्के टैंक और माउंटेड गन प्रणाली से युक्त होगी। इन स्वीकृत प्रस्तावों में हमारे सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा स्तर वाले बैलिस्टिक हेलमेट की खरीद भी शामिल है।

नौसेना की पोत-रोधी मिसाइलों, बहुउद्देश्यीय पोतों और उच्च सहनशक्ति वाले स्वायत्त वाहनों की खरीद के लिए दी गई इस मंजूरी से भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देने वाली समुद्री ताकत में और अधिक बढ़ोतरी होगी।

मिसाइल प्रणाली की नई रेंज, लंबी दूरी के निर्देशित बम, पारंपरिक बमों के लिए रेंज संवर्द्धन किट और उन्नत निगरानी प्रणाली को शामिल करके भारतीय वायु सेना को और अधिक घातक क्षमताओं के साथ मजबूत किया जाएगा। भारतीय तट रक्षक के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद तटीय क्षेत्रों में निगरानी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक बढ़ाएगी। ■

संयुक्त राष्ट्र ने 'नमामि गंगे' को विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में दी मान्यता

'नमामि गंगे' को दुनिया की 10 शीर्ष ईकोसिस्टम बहाली पहलों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त होना भारत सरकार के 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' द्वारा नदी के इकोसिस्टम की बहाली के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों का प्रमाण है

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए 'नमामि गंगे' पहल को प्राकृतिक को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी। 'नमामि गंगे' के महानिदेशक श्री जी. अशोक कुमार ने 14 दिसंबर, 2022 को विश्व बहाली दिवस के अवसर पर मॉन्ट्रियल (कनाडा) में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया।

'नमामि गंगे' को दुनिया के 70 देशों की 150 से अधिक ऐसी पहलों में से चुना गया है। इन पहलों को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र ईकोसिस्टम बहाली दशक बैनर के तहत चयन किया गया था। इसे पूरे विश्व में प्राकृतिक स्थानों के क्षरण की रोकथाम और बहाली के लिए तैयार किया गया है।

'नमामि गंगे' सहित सभी मान्यता प्राप्त पहलें अब संयुक्त राष्ट्र की सहायता, वित्त पोषण या तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने की पात्र होंगी।

गौरतलब है कि 'नमामि गंगे' को दुनिया की 10 शीर्ष ईकोसिस्टम बहाली पहलों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त होना भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नदी के इकोसिस्टम की बहाली के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों का प्रमाण है।

'नमामि गंगे': एक नजर

- 'नमामि गंगे' को दुनिया के 70 देशों की ऐसी ही 150 से अधिक पहलों में से चुना गया
- यह मान्यता नदी ईको सिस्टम की बहाली के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयासों का प्रमाण देती है
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा नदी को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए वर्ष 2014 में 'नमामि गंगे' कार्यक्रम शुरू किया था और गंगा नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए 5 बिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई थी
- 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के प्रति इतनी अटूट प्रतिबद्धता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में स्वयं राष्ट्रीय गंगा परिषद् द्वारा इसकी बहुत सुक्ष्मता से निगरानी की जाती है
- प्रधानमंत्री को जो उपहार प्राप्त होते हैं उनकी प्रति वर्ष सार्वजनिक नीलामी की जाती है और उससे प्राप्त आय गंगा नदी को साफ करने के सरकारी प्रयास में सार्वजनिक योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से गठित स्वच्छ गंगा कोष में दे दी जाती है ■

देश में 413 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय सहित 733 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का हो रहा संचालन

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रीजीजू ने 22 दिसंबर को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचित किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की स्थापना और इसका संचालन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है, जो अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार तथा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से इस तरह की अदालतों की स्थापना करती हैं।

उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार 2017 के बाद 242 और एफटीसी की स्थापना की गयी है। (31.12.2017 तक 596 एफटीसी मौजूद थे, जो 31.10.2022 तक बढ़कर 838 हो गए हैं)। केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2019 में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की, जिसमें 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 389 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय शामिल हैं, जो दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित जांच और निपटान के लिए हैं तथा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान 1/2019 दिनांक 25.7.2019 के निर्देशानुसार संचालित हैं।

प्रारंभ में यह योजना 1 वर्ष के लिए थी, जिसे अब 31.03.2023 तक के लिए जारी रखा गया है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 413 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित 733 एफटीएससी संचालित किये जा रहे हैं, जिन्होंने योजना की शुरुआत के बाद से कुल 1,24,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है और इन अदालतों में 31.10.2022 तक 1,93,814 मामले लंबित हैं। ■

'एक देश एक राशन कार्ड' के तहत अब तक किए गए 93.31 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन

'एक देश एक राशन कार्ड' योजना वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए देश भर के सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है

केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 14 दिसंबर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए 'एक देश एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना वर्तमान में कुल एनएफएसए आबादी (लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों) को कवर करते हुए देश भर के सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। वर्तमान में देश में ओएनओआरसी के अंतर्गत हर महीने औसतन लगभग 3.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किये जा रहे हैं। 'एक देश एक राशन कार्ड' के तहत अब तक कुल 93.31 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन पूरे हो चुके हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रौद्योगिकी से संचालित होने वाली 'एक देश एक राशन कार्ड' प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) के तहत सभी लाभार्थी विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सभी लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) से या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ आधार संख्या के द्वारा किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने मासिक आवंटन के खाद्यान्न को आंशिक या पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा, लाभार्थी के परिवार के जो भी सदस्य घर पर होंगे (यदि कोई हो) तो वे उसी राशन कार्ड पर खाद्यान्न का बचा हुआ हिस्सा/शेष खाद्यान्न या संपूर्ण खाद्य पदार्थ उठा सकते हैं।

राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए 'एक देश एक राशन कार्ड' योजना विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस) के तहत लागू की गई है, जिसे अप्रैल 2018 में 127.3 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृति दी गई थी।

इस योजना को 31 मार्च, 2023 तक विस्तार दिया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 2020-21 में (12.65 करोड़ रुपये), 2021-22 में (23.76 करोड़ रुपये) और 2022-23 में (10.45 करोड़ रुपये) अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा एनआईसी/एनआईसीएसआई आदि को कुल 46.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि जारी की गई है।

एनएफएसए लाभार्थियों के बीच एक देश एक राशन कार्ड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। इसके लिए 167 एफएम और 91 सामुदायिक रेडियो स्टेशन की सहायता ली जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर ऑडियो विजुअल स्पॉट प्रदर्शित किए जा रहे हैं। बाहरी स्थानों और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस), बस आदि में बैनर व पोस्टर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ऐसे विशेष अभियानों के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपने स्वयं के साधनों का उपयोग भी किया जा रहा है। 13 भाषाओं में उपलब्ध 'मेरा राशन' ऐप को भी अब तक लगभग 20 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है। ■

भारतीय नौसेना को पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वागीर' की डिलीवरी

प्रोजेक्ट-75 कलवरी क्लास सबमरीन की पांचवीं पनडुब्बी 'यार्ड 11879' 20 दिसंबर, 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई। प्रोजेक्ट-75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई में किया जा रहा है। 12 नवंबर, 2020 को लॉन्च की गई वागीर ने 1 फरवरी, 2022 से समुद्री परीक्षण शुरू किया और यह बहुत गर्व की बात है कि इस पनडुब्बी ने पहले की पनडुब्बियों की

तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा किया है।

पनडुब्बी निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि कठिनाई तब बढ़ जाती है जब सभी उपकरणों को छोटा करने की आवश्यकता होती है और कड़े गुणवत्ता की आवश्यकताएं भी बनाए रखनी होती है। एक भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम है और इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाता है, एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि यह 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी पनडुब्बी है।

पनडुब्बी को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और इससे भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। ■

सांसदों के लिए विशेष लंच के माध्यम से पोषक-अनाज को बढ़ावा देने की बड़ी पहल

मिलेट्स का मूल भारत है, जिनकी पोषक-अनाज के रूप लोकप्रियता रही है

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर को संसद परिसर में सांसदों के लिए 'विशेष मिलेट्स लंच' आयोजित कर देश-दुनिया में मिलेट्स को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की गई। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष मनाने की तैयारी की दृष्टि से आयोजन में उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता श्री अधीरंजन चौधरी, राज्यसभा में सदन के नेता व केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल सहित अन्य मंत्रियों व राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों ने शामिल होकर ज्वार, बाजरा, रागी जैसे पोषक-अनाज से तैयार व्यंजनों का स्वाद लिया और दिल खोलकर इनकी तथा समग्र आयोजन की तारीफ की व मिलेट्स ईयर का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री एवं अन्य नेतागण संसद में दोपहर के भोजन में हुए शामिल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अन्य नेताओं के साथ संसद में दोपहर के भोजन में शामिल हुए, जहां मिलेट्स से तैयार व्यंजन परोसे गए। अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जबकि हम 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं संसद में एक शानदार दोपहर के भोजन में शामिल हुआ, जहां मिलेट्स से तैयार व्यंजन परोसे गए। इसमें दलगत भावना से हटकर हुई भागीदारी को देखकर अच्छा लगा।

वर्ष 2023 अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित

प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल तथा भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, जिसे देशभर के साथ ही वैश्विक स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोरों पर चल रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिलेट्स की मांग और स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से इसके विषय में जागरूकता के प्रसार के लिए सभी के साथ मिलकर अनेक कदम उठा रहा है।

केंद्रीय मंत्री तोमर का कहना है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी चाहते हैं हमारे प्राचीन पोषक-अनाज को भोजन की थाली में पुनः सम्मानजनक स्थान मिलें। साथ ही, यह पहल दीर्घकाल में मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करेगी।

यह उत्सवीय वर्ष मनाने की पूर्व तैयारी के मद्देनजर मिलेट्स से बने सुस्वादु व्यंजनों के साथ संसद परिसर में सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के विशेष सान्निध्य में मंत्रियों-सांसदों सहित दोनों सदनों में विभिन्न दलों के नेताओं ने मिलेट्स का स्वादानुभव किया। लंच में भारतीय पोषक-अनाज से बनाए गए विभिन्न प्रकार के शानदार व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए क्यूरेटेड मिलेट्स-आधारित बुफे के तहत कई आयटम्स परोसी गई।

संसद के प्रांगण को मिलेट्स आधारित रंगोली से खूबसूरती से सजाया गया था और देशभर की प्राथमिक पोषक-अनाज फसलों को यहां प्रदर्शित किया गया, जिसका अवलोकन उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ व प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित हितधारकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष के लिए विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों का एक चित्र कोलाज भी यहां प्रदर्शित किया गया। कर्नाटक व राजस्थान के रसोइयों के समूहों ने आयोजन के लिए विभिन्न व्यंजन बनाएं।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा हाल ही में रोम (इटली) में अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था। मिलेट्स प्राचीन व शुष्क भूमि की महत्वपूर्ण फसलें हैं। छोटे दाने वाली इन अत्यधिक पौष्टिक अनाज-खाद्य फसलों को कम वर्षा में सीमांत मिट्टी/कम उपजाऊ मिट्टी व उर्वरक तथा कीटनाशक जैसे इनपुट की कम मात्रा में उगाया जाता है।

मिलेट्स का मूल भारत है, जिनकी पोषक-अनाज के रूप लोकप्रियता रही है, क्योंकि सामान्य कामकाज के लिए ये आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मिलेट्स एशिया एवं अफ्रीका में कृषि के रूप में अपनाई जाने वाली पहली फसल थी, जो बाद में विश्वभर में विकसित सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में फैल गई। ■

मोदी स्टोरी

कैसे मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कच्छ सीमा पर जवानों के लिए ताजा दूध उपलब्ध कराया

आदित्य चौहान

इस बात से हम सभी परिचित हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सीमा पर जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाते आये हैं। इस साल वह अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देश की रक्षा में तैनात जवानों के साथ रोशनी का त्योहार मनाने के लिए कारगिल गए। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जवानों को अपने परिवार के तौर पर परिभाषित करते हुए कहा कि उनके यहां आए बिना उनका त्योहार अधूरा है।

कुछ लोगों की यह धारणा भी हो सकती है कि श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जवानों से मिलना शुरू किया, परन्तु यह सच नहीं है।

गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जब वे भाजपा महामंत्री थे, तो पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उनकी सेवा की।

यह किस्सा है जिससे हमें पता चलता है कि जब श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कैसे कच्छ सीमा पर जवानों को ताजा दूध उपलब्ध करवाया।

उत्तराखंड के भाजपा नेता श्री आदित्य चौहान ने हरिद्वार में प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ अपनी मुलाकात की चर्चा की। श्री चौहान के बड़े भाई बीएसएफ में हैं और कच्छ सीमा पर सेवा दे चुके हैं। वह अक्सर श्री चौहान से इस बात का जिक्र करते थे कि मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी त्योहारों पर उनसे मिलने आते थे।

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कच्छ में भारत-पाकिस्तान सीमा का दौरा किया

> **कुछ लोगों की यह धारणा भी हो सकती है कि श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जवानों से मिलना शुरू किया, परन्तु यह सच नहीं है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जब वे भाजपा महामंत्री थे, तो पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उनकी सेवा की**

ऐसी ही एक घटना है, जब मुख्यमंत्री श्री मोदी कच्छ के दौरे पर थे और इस दौरान वहां तैनात जवान उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री मोदी के समक्ष दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। पहला यह कि पूरा इलाका दलदली होने के कारण इस इलाके में बिजली की समस्या थी। उनकी इस मांग पर मुख्यमंत्री श्री मोदी ने जवानों के लिए इनवर्टर और चार्जर उपलब्ध कराया।

एक अन्य जवान ने वहां उपलब्ध पैकेज्ड दूध के बजाय ताजा दूध की उपलब्धता का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जवानों को ताजा दूध देने के लिए गायों की उपलब्धता की बात कही।

श्री आदित्य चौहान श्री नरेन्द्र मोदी के इन कदमों को उत्साहजनक बताते हैं क्योंकि उन्होंने न केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात केंद्रीय बलों के साथ संवाद स्थापित किया बल्कि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आगे भी आए। ■

सामूहिकता का भाव

पं. दीनदयाल उपाध्याय

गतांक से...

इसी प्रकार जब द्रोणाचार्य यहां पर आए तो सीधी बात है कि द्रोणाचार्य को पुत्र का मोह था। भाई, अपने सेनापति को पुत्र का मोह, क्या वास्तव में मोह करने की जरूरत है? अगर सेनापति पुत्र का मोह लेकर चलेगा, तो क्या वह लड़ाई लड़ सकता है। उसको तो सब कुछ अपने समष्टि का विचार करना चाहिए, परंतु नहीं, वह अपने पुत्र के मोह को नहीं छोड़ सके, अरे इतने लोग मारे गए, तब दुःख नहीं हुआ, परंतु जब पुत्र मारा गया तो व्याकुल होकर शस्त्र छोड़ बैठे और दूसरी तरफ युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी, जिसके बारे में कहते थे कि उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और जिसके कारण कहते थे कि उनका रथ पृथ्वी से छह इंच ऊपर चलता था, परंतु फिर भी उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि युधिष्ठिर का क्या होगा? दुनिया क्या कहेगी? उन्होंने कहा कि भाई, ठीक है, यह समष्टि का ही काम है, भगवान् कृष्ण का आदेश है। इसको करूंगा। उसे अपने नाम की चिंता नहीं थी, कीर्ति की चिंता नहीं थी। अपना नाम लेकर के और 'नरो व कुंजरो', झूठ ही क्यों न बोल दिया हो।

अब द्रोणाचार्य व्यक्तिवादी थे और युधिष्ठिर, यह समष्टिवादी धर्म, समाज का विचार, समूह का विचार करके चलते थे, व्यक्ति का विचार नहीं। वही बात कर्ण की है। आपको मालूम होगा कि कर्ण के पास कवच और कुंडल थे। वे कवच और कुंडल ऐसे थे कि जब तक वे उसके पास रहते, तो कोई उसका किसी भी प्रकार से अहित नहीं कर सकता था। सूर्य के दिए हुए कवच और कुंडलों के बारे में इंद्र को पता था। इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के यहां गए। भगवान् सूर्य को यह बात पता लग गई कि यह होगा और इंद्र ऐसा करनेवाले हैं, कवच और कुंडल मांगनेवाले हैं तो उन्होंने कर्ण से कहा कि तू कुछ भी करना, लेकिन अपने कवच और कुंडल

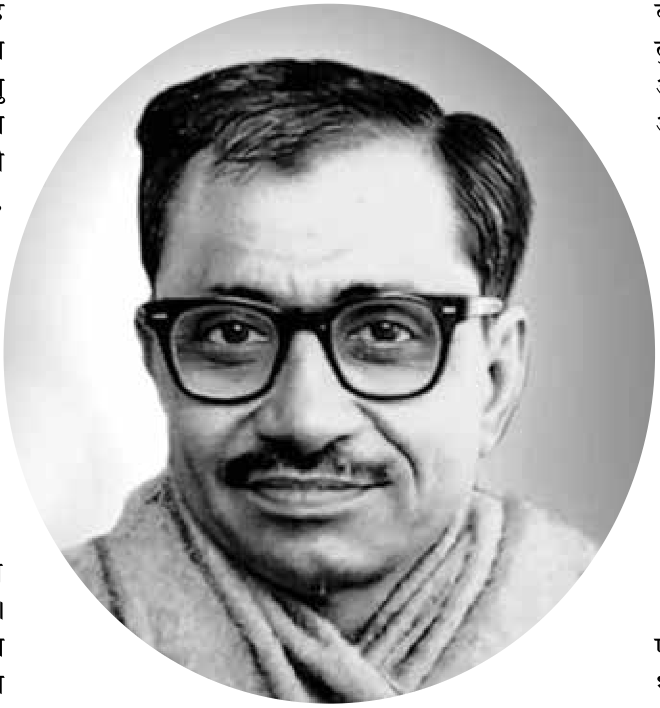

बिल्कुल मत देना। इतनी चेतावनी के बाद भी जब इंद्र वहां पहुंचे और उनसे कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण ने अपने कवच और कुंडल उनको दे दिए। क्योंकि उसको लगा कि मैं दानवीर हूं और मुझसे कोई मांगे और मैं न दूं? कर्ण दानवीर कर्ण तो हो गया, पर जिस पक्ष को ग्रहण किया था, जिस समाज का वह अंग बनकर खड़ा हुआ था, उसी का नहीं हुआ। वह भी व्यक्तिवादी रहा। इंद्र को भी सोचना चाहिए था कि मैं इंद्र जैसा व्यक्ति, देवताओं का राजा और ब्राह्मण का रूप धारण करके भीख मांगने गया, उन्होंने चिंता नहीं की। क्या यह काम धर्म का काम है?

कुंती के बारे में आपको मालूम है? कर्ण कुंती का बेटा था और जब वह कुंआरी थी, तब पैदा हुआ था और उस समय केवल लोकापवाद के डर से कि दुनिया क्या कहेगी, इसलिए उसने अपने पेट के लाड़ले को नदी के अंदर बहा दिया। यानी मां द्वारा अपने बच्चे को नदी के अंदर बहाना कितना बड़ा कठोर कर्म है, परंतु उसी कुंती ने बाद में जब अवसर आया, कर्ण के सामने जाकर यह बात कही कि तू मेरा बेटा है। अगर कुंती यह रहस्योद्घाटन न करती तो दुनिया को यह पता भी न होता कि वह कुंती का बेटा है। कुंती ने अपने माथे के ऊपर कालिख पोत ली, लेकिन केवल इसलिए कि एक सामूहिक ध्येय सामने रखा था, वह पूरा हो जाए। वह कर्ण से यह वचन लेकर आई थी कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी पर बाण नहीं चलाएगा। यानी बाक़ी के सब अपने पुत्रों का अभयदान उसने मांग लिया। आप वही देखेंगे कि भगवान् कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा की थी कि 'मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा', परंतु जब मौक़ा आ गया तब तो भीष्म के ऊपर वे भी शस्त्र लेकर दौड़ पड़े, यानी भगवान् ने अपनी प्रतिज्ञा की चिंता नहीं की; परंतु भीष्म ने प्रतिज्ञा की चिंता की ऐसा लगता

है कि वहां जितने भी कौरव पक्ष में थे, वे बड़े-बड़े महारथी थे। इधर तो कुछ नहीं थे, उनके मुक़ाबले में यानी मैन टू मैन कहेंगे, एक-एक व्यक्ति का मुकाबला करेंगे तो इधर के पांडव पक्ष के एक-एक व्यक्ति से कौरव पक्ष का हर व्यक्ति ज्यादा निपुण था। ज्यादा वीर था। शूरता थी, सब कुछ थी, परंतु इतना होने के बाद भी अगर उनमें कुछ कमी थी, वह यह थी कि हर व्यक्ति था, वहां पर सब मिलकर कोई समूह नहीं था, समाज नहीं था, उनके अंदर कोई समष्टि भाव नहीं था। वे अलग-अलग थे, एक-एक करके हर कोई अपने नाम की चिंता करता था, कोई अपनी वीरता की चिंता करता था। किसी को अपने राज्य की चिंता नहीं थी। केवल दुर्योधन अपना राज्य चाहता था। इधर पांडव पक्ष में जितने थे, ये मिलकर एक थे और भगवान् कृष्ण को सबने नेता बनाया, बस उसकी जो आज्ञा है उसका पालन करेंगे, यह विश्वास था। विचार लेकर चले थे। किसी ने अपने नाम की चिंता नहीं की। किसी ने कहा कि भाई झूठ बोलना है, तो झूठ बोला, किसी ने कहा कि गदायुद्ध के नियमों का उल्लंघन करना है, उसने नियमों का उल्लंघन किया, किसी ने कहा कि तुम्हें जाकर कर्ण से भीख मांगनी है, तो उसने जाकर भीख मांगी, किसी ने कहा कि तुम्हें रहस्योद्घाटन करना है, तो रहस्योद्घाटन किया। खुद द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गई और उसने जाकर पूछा कि तुम्हारी मृत्यु का रहस्य क्या है यह तो बताओ, भीष्म पितामह तो खुद बताने लगे कि अगर शिखंडी सामने आ जाएगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। मृत्यु का यह रहस्य द्रौपदी ने पूछा। अब इतना सब कुछ हुआ। और आप वहां पर देखेंगे, तो सब लोग एक गुट होकर काम करनेवाले समष्टिवादी थे।

वास्तव में समष्टिवाद ही धर्म है। राष्ट्रवाद धर्म है। समूह के लिए राष्ट्र के लिए काम करना, यह धर्म है। व्यक्ति के लिए और व्यक्ति का ही विचार करके काम करना, यह अधर्म है। मोटी सी व्याख्या है। एक ही व्याख्या है कि सच्चाई और झूठ का समष्टिभाव।

जिसको लोग सच कहते हैं, सामान्य जीवन के लिए यह ठीक है। रोज के जीवन में यदि कोई कहेंगे तो भगवान् कृष्ण ने झूठ बुलवाया या युधिष्ठिर ने झूठ बोला तो हम भी रोज झूठ बोलें, तो रोज झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। यह निर्णय राष्ट्र का विचार करके होगा। हरेक स्थिति का नियम है, लड़ाई होती है, लड़ाई में सिपाही गोली चलाकर नर हत्या करता है। यानी दुश्मन के ऊपर गोली चलाता है। अब आप यह कहेंगे कि वाह-वाह सिपाही आखिर रोज़ हिंसा करता है। हम भी हिंसा कर डालें तो? आपको मार डाले तो? मगर आप नहीं मार सकते हैं यानी सिपाही की हिंसा, वह

वास्तव में समष्टिवाद ही धर्म है। राष्ट्रवाद धर्म है। समूह के लिए राष्ट्र के लिए काम करना, यह धर्म है। व्यक्ति के लिए और व्यक्ति का ही विचार करके काम करना, यह अधर्म है। मोटी सी व्याख्या है। एक ही व्याख्या है कि सच्चाई और झूठ का समष्टिभाव

हिंसा नहीं है। सिपाही की हिंसा और उसने कितने ज्यादा लोग मारे, इसके ऊपर तो उसको परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। अगर आप किसी को मार डालें तो आपको बिल्कुल फांसी की सजा हो जाएगी। दोनों में फर्क हो जाता है, यानी वह राष्ट्र के लिए करता है, इसलिए उसका नाम होता है। राष्ट्र के लिए करता है, इसलिए उसकी हिंसा हिंसा नहीं होती। वही काम अगर कोई राष्ट्र के विरोध में करेगा, तो वह फिर हिंसा मानी जाती है।

कौन सी चीज़ हिंसा है, कौन सी चीज़ हिंसा नहीं है। दुश्मन के यहां जाकर लोग जासूसी करते हैं। तरह-तरह की चीजें करते हैं। अनेक प्रकार के जिनको कुकर्म कहा जाता है, वे कर्म भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करके लाते हैं, परंतु दुश्मन के यहां से कोई चोर उनके रहस्य को चुराकर ले आया या फाइल चुराकर ले आया तो क्या उसको लोग चोर कहेंगे? कहेंगे कि तुमको तो इंडियन पीनल कोड के अनुसार सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि तुम तो वहां से फाइल चुराकर लाए थे, ऐसे व्यक्ति का तो आप सम्मान करेंगे, परंतु अगर वही व्यक्ति यहां पर किसी की जेब में से उसकी चीज़ चुरा लेगा तो उसे दंड दिया जाएगा, यानी वह चोरी है और वहां से दुश्मन के यहां से चुराकर लाया, तो वह चोरी नहीं है। क्योंकि वह राष्ट्र के लिए है। एक राष्ट्र के लिए है और दूसरी नहीं।

सबसे बड़ा वैभव है राष्ट्र का वैभव। उसके लिए काम किया जाए, वही ताक़त है। ताक़त भी अगर कोई कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से काम, वह ताक़त नहीं, उससे आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती, उसमें शक्ति भी नहीं है। जब हम सामूहिक रूप से काम करेंगे और इसलिए हमने अपनी प्रार्थना में दूसरी बात साथ-साथ में कही है कि संगठन कार्य शक्ति है। हमने भगवान् से यह नहीं कहा है कि हे भगवान्, हमें वैभव दे दीजिए। यह हमने नहीं कहा, बल्कि हमने अपने मन की कामना का उल्लेख किया है। हमने आशीर्वाद मांगा है। साथ ही, हमने यह बात कह दी है कि संगठित कार्य शक्ति निश्चित रूप से विजयशाली होती है। जहां पर संगठित कार्यशक्ति नहीं होगी, सामूहिक शक्ति नहीं होगी, वहां पर विजय नहीं मिलेगी, इस एक बात को समझ करके हम चलें।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वास्तव में संपूर्ण समाज में यही एक भाव पैदा करता है, राष्ट्रीयता का भाव। यह राष्ट्रीयता का भाव ऐसा है कि जिसके आधार पर बाक़ी की सब चीजें ठीक हो सकती हैं। यह एक भाव नहीं रहा तो बाक़ी की सब चीजें अच्छी से अच्छी चीजें भी बेकार हैं। ■

क्रमशः...

-शीत शिविर वर्ग, बौद्धिक वर्ग: फरवरी 4, 1968

केंद्रीय गृहमंत्री ने की भारतीय सेना की वीरता की सराहना एवं विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा पर हुए चीनी सैनिकों के अतिक्रमण के कुप्रयास को भारतीय सेना द्वारा विफल कर दिए जाने के पश्चात् 13 दिसंबर, 2022 को भारतीय सेना के शौर्य एवं वीरता की भूरि-भूरि सराहना की और संसद परिसर में मीडिया को संबोधित कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

श्री शाह ने संसद परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज संसद में प्रश्नकाल को विपक्ष और ख़ास कर कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं चलने दिया गया। मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस कुप्रयास की घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत-चीन सीमा पर बीते 8 दिसंबर की देर रात और 9 दिसंबर की सुबह के दरम्यान घटी हुई घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने प्रश्नकाल को स्थगित कराया, जिसका कोई औचित्य नहीं था। जब संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्टता से कह दिया था कि आज दोपहर 12:00 बजे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे, तो विपक्ष द्वारा प्रश्नकाल को स्थगित करवाना कहीं से भी सही नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर, मैंने प्रश्नकाल की सूची को देखा तो पांचवें नंबर का प्रश्न देखकर इनकी चिंता समझ गया, क्योंकि प्रश्नकाल का पांचवां प्रश्न राजीव गांधी फाउंडेशन के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में था और कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था। इसका जवाब भी बहुत स्पष्ट था। अगर मौक़ा मिलता तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था, जो एफसीआरए क़ानून के अनुरूप नहीं था।

> **नेहरू जी के चीन प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता की बलि चढ़ गई। इस विषय को राजीव गांधी फाउंडेशन ने अपने शोध का विषय बनाया था क्या और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ?**

उन्होंने कहा कि चूंकि चीनी दूतावास द्वारा कांग्रेस पार्टी को मिला अनुदान एफसीआरए क़ानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो इसलिए इस संदर्भ में नोटिस देकर, पूर्णतया कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। राजीव गांधी फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया था, लेकिन जो राशि चीनी दूतावास से इस फाउंडेशन को मिली थी, वह फाउंडेशन को भारत-चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या शोध किया?

- 1962 में भारत की जो हजारों हेक्टेयर की भूमि चीन ने हड़प ली थी, क्या इस विषय को अपने शोध में शामिल किया था? और यदि इस विषय पर राजीव गांधी फाउंडेशन ने शोध किया तो रिपोर्ट क्या आई?
- नेहरू जी के चीन प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता की बलि चढ़ गई। इस विषय को राजीव गांधी फाउंडेशन ने अपने शोध का विषय बनाया था क्या और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ?
- जिस वक्त गलवान में हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था। वह, राजीव गांधी फाउंडेशन के शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका निष्कर्ष क्या निकला?
- जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर अपना दावा कर दिया था, क्या इस विषय को राजीव गांधी फाउंडेशन ने अपने शोध में शामिल किया था? यदि किया था, तो इस पर क्या निष्कर्ष निकला?
- 25 मई, 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खांडू को वीजा देने से इनकार कर दिया यह मानते हुए कि अरुणाचल तो हमारा ही हिस्सा है। इस पर फाउंडेशन ने शोध किया क्या?
- 13 अक्टूबर, 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई थी। उस पर राजीव गांधी फाउंडेशन ने

राहुल गांधी का बयान सेना के मनोबल को तोड़ने वाला : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 दिसंबर, 2022 को प्रेस वक्तव्य जारी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश की जांबाज सेना के अपमान वाली टिप्पणी की कड़ी शब्दों में निंदा की।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का देश की सेना के मनोबल को तोड़ने वाला बयान सर्वथा निंदनीय और देश की एकता एवं अखंडता पर प्रश्न चिह्न लगाने वाला है। यह देश के वीर जवानों का अपमान है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एवं निंदा की जाए, वह कम है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। जब भी देश पर संकट आया है, देश की सेना ने अपना सर्वस्व अर्पित कर देश की रक्षा की है। हमें अपनी सेना पर गर्व है।

उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया था। देश की जनता यह भी जानती है कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फांउडेशन को किस तरह से आर्थिक फंडिंग और मदद की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार-बार चीन की भाषा बोलते हैं।

उन्होंने कहा कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय राहुल गांधी रात के अंधेरे में चुपचाप चीनी दूतावास में चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितने प्रश्नचिह्नों से घिरी है। उन्होंने सर्जिकल स्टाइक और एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। यह बताता है कि राहुल गांधी भारत की भाषा नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी वो भाषा बोलते हैं जो चीन और पाकिस्तान बोलता है।

श्री नड्डा ने कहा कि मैं पुनः राहुल गांधी के इस शर्मनाक बयान की कड़ी भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी का यह बयान देश की सेना के प्रति उनकी मानसिकता और उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। ■

शोध किया था क्या?

- 2011 में कांग्रेस की सरकार ने चीन की धमकी के बाद डेमचोक में हमारे रोड और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रोक दिया। यह क्यों रोका गया? राजीव गांधी फाउंडेशन ने इस विषय पर शोध किया क्या?

कांग्रेस पार्टी पर हमला जारी रखते हुए श्री शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि यह दोहरा और दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। कांग्रेस पार्टी के एक परिवार द्वारा चलाये जा रहे राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन को चीनी दूतावास से मिले हुए अनुदान के कारण समाप्त हुआ है। कांग्रेस की ही सरकार के समय में देश की हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से चीन द्वारा हड़प ली गई। कांग्रेस के ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद् की सदस्यता अपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन को भेंट दे दी गई। देश की जनता इन सारे विषयों को जानती और समझती है।

उन्होंने कहा कि मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, देश की एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। 08 दिसंबर की देर रात और 09 दिसंबर की सुबह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत-चीन सीमा पर हमारे वीर जवानों ने जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरि-भूरि सराहना करता हूं और अपने जवानों के शौर्य को सलाम करता हूं कि उन्होंने घुसे हुए चीनियों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और मातृभूमि की रक्षा की।

श्री शाह ने कहा कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से 7 जुलाई, 2011 को 50 लाख रुपये का अनुदान मिला था। मैं पूछना चाहता हूं राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के कर्ताधर्ता से जो फैमिली पार्टी कांग्रेस के उस परिवार के ही सदस्य हैं, कि आपको यह पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया था? इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। ■

पूर्वोत्तर दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए हमारा प्रवेश द्वार है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 दिसंबर को शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद् (एनईसी) की बैठक को संबोधित किया। यह बैठक पूर्वोत्तर परिषद् के स्वर्ण जयंती समारोह का प्रतीक है, जिसका औपचारिक उद्घाटन 1972 में हुआ था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में पूर्वोत्तर परिषद् के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका यह स्वर्ण जयंती समारोह चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के साथ आयोजित किया जा रहा है।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वे अक्सर क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्ट लक्ष्मी के रूप में संदर्भित करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इसके विकास के लिए 8 आधार स्तंभों अर्थात— शांति, बिजली, पर्यटन, 5जी कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल की क्षमता पर काम करना चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए हमारा प्रवेश द्वार है और पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की इस संभावना को साकार करने के लिए भारतीय-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और अगरतला-अखौरा रेल परियोजना जैसी परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार 'लुक ईस्ट' नीति को 'एक्ट ईस्ट' में बदलने से आगे निकल गई है और अब इसकी नीति 'एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ-ईस्ट' और 'एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ-ईस्ट' है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, अंतरराज्यीय सीमा समझौते किए गए हैं और उग्रवाद की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। ■

मोदी सरकार में उत्तर-पूर्व शांति बहाली के साथ ही विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है : अमित शाह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 18 दिसंबर को मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद् के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। इस मौके पर मेघालय के राज्यपाल ब्रिगेडियर (डॉ.) बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा एवं अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कालखंड में ही 2019 में एनएलएफटी से समझौता, 2020 में ब्रू व बोड़ो समझौता, 2021 में कार्बी समझौता और असम-मेघालय व असम-अरुणाचल सीमा के विवाद भी लगभग समाप्त हो गए हैं और उत्तर-पूर्व शांति बहाली के साथ ही विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पहले उत्तर-पूर्व से AFSPA को हटाने के लिए डिमांड आती थी, अब डिमांड नहीं आती बल्कि भारत सरकार दो कदम आगे बढ़कर AFSPA हटाने के लिए इनीशिएटिव ले रही हैं।

उन्होंने कहा कि आज असम के 60% क्षेत्र, नागालैंड के 7 जिले, मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन और त्रिपुरा व मेघालय पूर्णतया अफस्पा मुक्त हुए हैं तो अरुणाचल में एक ही जिला अफस्पा मुक्त होने से बाकी बचा है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि उत्तर-पूर्व के विकास के लिए मोदी जी ने NEC के सामने जो लक्ष्य रखें हैं, उन्हें NEC व उत्तर-पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री समय पर पूर्ण करने के लिए संकल्पित होकर कार्य करेंगे और नॉर्थ-ईस्ट को देश के अन्य हिस्सों की तरह विकसित, शांत, रोजगार युक्त क्षेत्र बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे।

'त्रिपुरा गरीबों के लिए घर बनाने में अग्रणी राज्यों में एक है'

ई-कोर्ट परियोजना के तहत अनेक नई पहलों का शुभारंभ

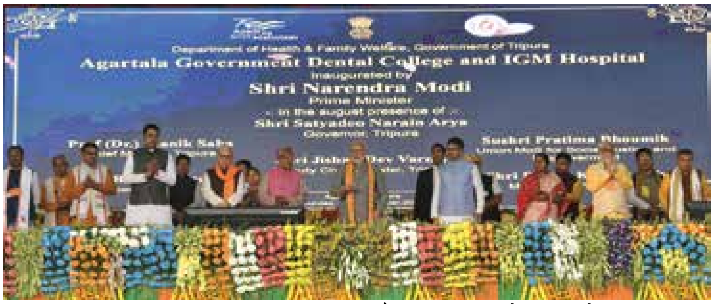

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 दिसंबर को 4350 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न प्रमुख पहलों का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी एवं ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ, अगरतला बाईपास (खैरपुर-अमतली) एनएच-08 के चौड़ीकरण के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाएं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना III के तहत 230 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 32 सड़कों का शिलान्यास और 540 किलोमीटर से अधिक लंबाई को शामिल करते हुए 112 सड़कों के उन्नयन की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आनंदनगर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने समारोह के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार करने वाले उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया और मेघालय में व्यस्तताओं के कारण हुई थोड़ी देरी के लिए भी माफी मांगी, जहां उन्होंने मेघालय में दिन में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था।

श्री मोदी ने पिछले 5 वर्षों में स्वच्छता अभियानों के संबंध में राज्य में किए गए सराहनीय कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह त्रिपुरा के लोग हैं, जिन्होंने इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया है। इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि मां त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा की विकास यात्रा नई ऊंचाइयों को छू रही है।

प्रधानमंत्री ने आज की उन परियोजनाओं के लिए त्रिपुरा के लोगों को बधाई दी, जो कनेक्टिविटी, कौशल विकास और गरीबों के घर से जुड़ी योजनाओं से संबंधित हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने पर जोर देते रहे हैं कि हर किसी के पास अपना घर हो। इस क्षेत्र में इसे सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इन घरों का निर्माण 3400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है और 2 लाख से अधिक लाभार्थी इसमें शामिल होंगे।

सड़क संपर्क में सुधार पर ध्यान देने के साथ प्रधानमंत्री ने अगरतला बाईपास (खैरपुर-अमतली) एनएच-08 को चौड़ा करने के लिए परियोजना का उद्घाटन किया, जो अगरतला शहर में यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने पीएमजीएसवाई III (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के तहत 230 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 32 सड़कों और 540 किलोमीटर से अधिक की दूरी वाली 112 सड़कों के उन्नयन के लिए आधारशिला रखी। श्री मोदी ने आनंदनगर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया।

शिलांग में 2450 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 दिसंबर को मेघालय के शिलांग में 2450 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में 320 पूर्ण और 890 निर्माणाधीन 4जी मोबाइल टावरों का उद्घाटन, उमसावली में आईआईएम शिलांग का नया परिसर, नए शिलांग सैटेलाइट टाउनशिप को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शिलांग-दींगपसोह रोड और तीन राज्यों— मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के लिए चार अन्य सड़क परियोजनाएं शामिल हैं।

श्री मोदी ने मेघालय में मशरूम विकास केंद्र और एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में स्पॉन प्रयोगशाला और मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में छह सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने तुरा और शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क फेज-2 में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला भी रखी।

सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मेघालय एक ऐसा राज्य है, जो प्रकृति और संस्कृति में समृद्ध है और यह समृद्धि लोगों की गर्मजोशी और स्वागत करने वाले स्वभाव से परिलक्षित होती है। उन्होंने मेघालय के नागरिकों को राज्य में और भी अधिक विकास के लिए कनेक्टिविटी, शिक्षा, कौशल और रोजगार से लेकर कई आगामी और नई उद्घाटन की गई परियोजनाओं के लिए बधाई दी। ■

भारत की विदेश नीति में 2014 के बाद बदलाव आया: एस. जयशंकर

भाजपा ने आयोजित किया 'विदेश नीति संवाद'

भाजपा के विदेश मामलों के विभाग ने 17 दिसंबर, 2022 को 'विदेश नीति संवाद' का पहला सत्र आयोजित किया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस दौरान डॉ. एस. जयशंकर ने भाजपा मुख्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और भारत के अन्य प्रमुख संस्थानों के 'अंतरराष्ट्रीय संबंधों' के पाठ्यक्रम से जुड़े शोधार्थियों के साथ बातचीत की। कार्यक्रम में प्रारंभिक टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले ने 'विदेश नीति संवाद' के पीछे के विचार और उद्देश्य के बारे में बताया, उन्होंने कहा, 'विदेश नीति संवाद' के माध्यम से वैश्विक राजनीति के समकालीन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम व्यक्तियों के साथ शिक्षाविदों को जोड़ना है

अपने संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "इतिहास से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि हमने बाहरी दुनिया और 'पानीपत सिंड्रोम' के कारण लगातार खतरों को कम करके आंका है, जिसका अर्थ है कि जब तक दुश्मन वास्तव में आपके द्वार पर नहीं आ जाता है, तब तक अज्ञानता में रहना, इसे अब बदलना चाहिए।" उन्होंने अन्य देशों में होने वाली घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "चीन में शुरू हुई कोविड महामारी का पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा और रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभावस्वरुप मुद्रास्फीति, तेल की कीमतों में वृद्धि और आर्थिक अनिश्चितताएं पैदा हुईं। ऐसे ही आतंकवाद भी किसी भी दिन हमें प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि विदेश नीति राष्ट्रीय एकता पर निर्भर है। हर गुजरते साल के साथ भारत और अन्य देशों के बीच संबंध सुदृढ़ हो रहे हैं।

> **विदेश नीति राष्ट्रीय एकता पर निर्भर है। हर गुजरते साल के साथ भारत और अन्य देशों के बीच संबंध सुदृढ़ हो रहे हैं। दुनिया को एक कार्यस्थल के रूप में देखते हुए वैश्विक कार्यस्थल में भारतीय भागीदारी एक बड़ा अवसर लेकर आती है**

दुनिया को एक कार्यस्थल के रूप में देखते हुए वैश्विक कार्यस्थल में भारतीय भागीदारी एक बड़ा अवसर लेकर आती है और साथ ही, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिर्माण, कृषि को बढ़ावा देने, सेवा क्षेत्र और विदेशी निवेश का समर्थन कर रहे हैं।

पड़ोसियों तक पहुंच

- पड़ोसियों तक पहुंच के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 2014 से भारत की विदेश नीति बदली है। 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से हुई, जहां उन्होंने सभी पड़ोसी देशों को समारोह में आमंत्रित किया, जो भारत के कूटनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम था।
- पहले जब कुछ बुरा होता था तो हमारे पड़ोसी पश्चिम की ओर देखते थे, आज यह क्षेत्र भारत की ओर देखते हैं। नेपाल भूकंप आपदा, यमन युद्ध, श्रीलंका में

भूस्खलन, मालदीव जल संकट और मोजाम्बिक चक्रवात के दौरान भारत ने सबसे पहले इन देशों को सहायता प्रदान की।

दुनिया आज भारत को पहचानती है

- दुनिया आज जिस तरह से भारत को देख रही है, उसमें आए बदलाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, पहले हम एक बैक ऑफिस थे, अब हम फार्मेसी, इनोवेशन और रिसर्च में लीडर हैं।
- वैक्सीन मैत्री और योग जैसी पहलों से भारत की छवि बदली है।
- विश्व की अपेक्षाएं हैं और चूंकि हम एक सभ्यतागत राष्ट्र हैं, इसलिए हमारा व्यक्तित्व, विरासत और संस्कृति मायने रखती है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कूटनीति, सुरक्षा, सेना और खुफिया तंत्र मिलकर काम कर रहे हैं और मजबूत हुए हैं।
- 2014 के बाद से हमारी छवि, हमारा उद्देश्य, हमारा आत्मविश्वास और जिस तरह से बाकी दुनिया हमें देखती है, इन सभी में बदलाव आया है।

भारत-चीन संबंध

इस चर्चा के अगले भाग में डॉ. एस. जयशंकर ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को संबोधित किया।

- भारत-चीन संबंधों से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, “हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र मूलभूत इकाइयां हैं जो अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। चीन के साथ संबंधों के प्रतिस्पर्धी पहलू हैं, जो 1950 के दशक में महसूस नहीं किए गए थे।”

भारत-चीन सीमा विवाद

- भारत-चीन सीमा विवाद के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि 1950 के बाद हमारी सीमाएं एक-दूसरे से सीधे जुड़ी हुई हैं, जो पारस्परिक रूप से निर्धारित नहीं थीं और इस प्रकार एक संघर्ष पैदा हुआ। 1962 के युद्ध का प्रभाव अभी भी संघर्ष पैदा कर रहा है क्योंकि इस दौरान भारतीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया था।
- दूसरी बात, चीन ने खासकर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत से पहले आर्थिक सुधार लागू किये। हालांकि, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारत को एक विनिर्माण केंद्र, प्रौद्योगिकी और नवाचार नेतृत्वकर्ता के तौर पर स्थापित कर रही है।

> **आतंकवादी घटना को अंजाम देने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी और भारत को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे पाकिस्तान को आतंकवाद से दूर ले जाया जा सके। भारत ने राजनीतिक एजेंडे पर ध्यान दिए बिना अफगानिस्तान के लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है**

भारत की विदेश नीति का भविष्य

- भारत की विदेश नीति के भविष्य के बारे में चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' प्रमुख कारक और बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो राष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे। उन्होंने भारतीय बाजार को हमारी सबसे बड़ी ताकत बताया।
- उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायों का समर्थन करना और ब्रांड बनाना, तकनीकी प्रगति और देश के भीतर आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत कर हम सम्मान अर्जित कर सकते हैं।

पाकिस्तान और आतंकवाद

- पाकिस्तान और आतंकवाद के संदर्भ में उन्होंने कहा कि आतंकवादी घटना को अंजाम देने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी, और भारत को ऐसे कदम उठाने होगें जिससे पाकिस्तान को आतंकवाद से दूर ले जाया जा सके। अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने राजनीतिक एजेंडे पर ध्यान दिए बिना अफगानिस्तान के लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है। हमने उन्हें गेहूं, वैक्सीन आदि भेजे हैं और हम काबुल में एक अस्पताल का संचालन भी कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम दवाओं की आपूर्ति भी कर रहे हैं।
- अफगानिस्तान में भारत की और अधिक भागीदारी की इच्छा रखता है। नेपाल में चीन के निवेश के मामले में उन्होंने कहा कि नेपाल, भारत और चीन दोनों का साझा पड़ोसी है। भारत यह उम्मीद नहीं कर सकता कि चीन नेपाल में निवेश नहीं करेगा। हमारी चुनौती लगातार यह साबित करना है कि हम नेपाल के लिए सबसे अच्छे भागीदार हैं।
- उन्होंने प्रतिभागियों से अपील करते हुए चर्चा को समाप्त किया कि छात्रों को भारत की विदेश नीति को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने वाले विचारों के साथ अपना योगदान देना चाहिए। विदेश नीति के महत्व से लोगों को अवगत कराने की जिम्मेदारी देश के युवाओं पर है।

विस्तृत चर्चा के बाद डॉ. एस. जयशंकर के साथ एक समूह तस्वीर ली गई और छात्रों को सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। ■

संसद के दोनों सदनों ने नौ विधेयक किए पारित

लोकसभा की उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत और राज्यसभा का लगभग 103 प्रतिशत रही

संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर, 2022 को शुरू हुआ और 23 दिसंबर, 2022 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र की 17 दिनों की अवधि में 13 बैठकें आयोजित हुईं।

केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने संसद परिसर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सत्र, जो मूल रूप से 7 दिसंबर, 2022 से 29 दिसंबर, 2022 तक 17 बैठकों को आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था, इसे आवश्यक सरकारी कार्य पूरा होने और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की सिफारिशों के कारण सत्र का समय कम किया गया। सदनों की कार्य मंत्रणा समिति ने क्रिसमस/साल के अंत में होने वाले समारोहों के लिए पार्टी लाइन से हटकर सांसदों की मांग और भावनाओं का संज्ञान लिया। केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय संसदीय कार्य और विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे।

सत्र के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और उन पर मतदान किया गया एवं संबंधित विनियोग विधेयकों को 11 घंटे चली बहस के बाद 14.12.2022 को लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा ने इन विधेयकों को करीब 9 घंटे की बहस के बाद 21.12.2022 को वापस कर दिया।

श्री जोशी ने यह भी कहा कि मौजूदा विधान को पूरक करते हुए और 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करते हुए तथा निगरानी तंत्र बेहतर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही में बढ़ोतरी करने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार आदि के लिए दो विधेयक 'बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022' और 'जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022' को जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए विश्वास-आधारित शासन को अच्छा बनाने के लिए नाबालिग अपराधों को कम करने और युक्तियुक्त बनाने के लिए कुछ विधानों में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को उनके प्रस्ताव के बाद संबंधित सदनों में पारित होने के बाद भेजा गया था।

संसद का शीतकालीन सत्र

दोनों सदनों द्वारा पारित प्रमुख विधेयक

केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 9 विधेयक पेश किए गए। लोकसभा ने 7 विधेयक और राज्यसभा ने 9 विधेयक पास किए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 9 है। सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित कुछ प्रमुख विधेयक निम्न हैं:

वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022: यह कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (ए): यह ऊर्जा और फीडस्टॉक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है; (बी) यह कार्बन बाजार स्थापित करने; (ग) बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाने; (डी) ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के दायरे को बढ़ाने; (ङ) जुर्माने के प्रावधानों में संशोधन करने; (च) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद् में सदस्यों की संख्या बढ़ाने; (छ) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को उनके कार्यों के निर्विघ्न निर्वहन के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त बनाने का जनादेश देता है।

नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022: यह केंद्र का नाम नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से बदलकर भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने का प्रस्ताव करता है, ताकि कानून द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की विशिष्ट पहचान स्पष्ट हो और अपने वास्तविक उद्देश्य को दर्शाता है।

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022: यह संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 में उत्तर प्रदेश के चार जिलों (i) चंदौली, (ii) कुशीनगर, (iii) संत कबीर नगर और (iv) भदोही

में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में बाहर करने और उन्हें इन चार जिलों में उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है।

मैरीटाइम एंटी-पायरेसी बिल, 2022: यह समुद्र में समुद्री डकैती के दमन के लिए विशेष प्रावधान करने और समुद्री डकैती के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करने और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव करता है।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022: यह संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करना चाहता है, ताकि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित किया जा सके व तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के सूची में नारिकोरवन और कुरीविककरण समुदायों को शामिल किया जा सके।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022: यह संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करना चाहता है, ताकि कर्नाटक राज्य के संबंध में बेट्टा-कुरुबा समुदाय के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन किया जा सके।

अल्पकालिक चर्चाएं

लोकसभा में नियम 193 के तहत दो अल्पकालिक चर्चाएं आयोजित की गईं:

i. देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या और उस पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम

ii. भारत में खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता और सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर आगे की चर्चा फिर से शुरू हुई और समाप्त हुई।

राज्यसभा में नियम 176 के तहत 'ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभाव और इससे निपटने के लिए उपचारात्मक कदमों की आवश्यकता' पर एक अल्पकालिक चर्चा आयोजित की गई।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा की उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत और राज्यसभा का लगभग 103 प्रतिशत रही।

शीतकालीन सत्र के दौरान संपन्न विधायी कार्य

लोक सभा में पेश किए गए विधेयक

- बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022
- विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022
- विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2022
- निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022

लोक सभा द्वारा पारित विधेयक

- विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022
- विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022
- समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

- वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022
- नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022
- विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022
- विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2022
- समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

- वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022
- नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022
- विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022
- विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022
- समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 ■

आज़ादी के अमृत काल के दौरान देश के पूर्वी क्षेत्र का भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 17 दिसंबर को कोलकाता में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों, बिहार के उपमुख्यमंत्री और ओडिशा के मंत्रियों सहित केन्द्रीय गृह मंत्रालय और परिषद् के अंतर्गत आने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

अपने उद्‌घाटन संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 1000 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई और उनमें से 93 प्रतिशत मुद्दों को सुलझा लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 से 2013 तक 8 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की कुल 6

बैठकें हुईं (औसतन प्रति वर्ष एक बैठक से भी कम), लेकिन 2014 से अब तक 8 वर्षों में कोविड-19 महामारी के बावजूद भी कुल 23 बैठकें (आज की बैठक सहित) हो चुकी हैं (औसतन 3 बैठकें प्रति वर्ष)।

श्री शाह ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने विगत वर्षों में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गतिशक्ति योजना की परिकल्पना में बड़ा हिस्सा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा इस क्षेत्र के विकास पर थ्रस्ट दिया है।

श्री शाह ने कहा कि अगले 25 वर्षों में आज़ादी के अमृत काल के दौरान देश के पूर्वी क्षेत्र का भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् बैठक अच्छे और सकारात्मक माहौल में हुई, कई मुद्दों पर सहमति बनी और बाकी बचे मुद्दों को भी विचार-विमर्श द्वारा सुलझा लिया जाएगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है और इस निर्णायक वर्चस्व को बनाए करने के प्रयास निरंतर रहने चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि वामपंथी उग्रवाद-मुक्त राज्यों में ये दोबारा ना पनपे और ये राज्य देश के अन्य हिस्सों के बराबर विकास करें। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)................................ (2)..............................

ईमेल : ....

सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :.................................. दिनांक :.............................. बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

नागपुर (महाराष्ट्र) में 12 दिसंबर, 2022 को एम्स और अन्य परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गोवा में 11 दिसंबर, 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह के दौरान तीन राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 13 दिसंबर, 2022 को वर्ष 2001 के संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अहमदाबाद (गुजरात) में 14 दिसंबर, 2022 को 'प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव' के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

शिलांग में 18 दिसंबर, 2022 को उत्तर पूर्वी परिषद् के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान एक समूह चित्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अगरतला (त्रिपुरा) में 18 दिसंबर, 2022 को एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह